



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जुलाई 8, 2004/आषाढ़ 17, 1926

No. 145]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 8, 2004/ASADHA 17, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2004

फा. सं. 2(29) बी (डी)/2004.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“बजट 2004-2005

वित्त मंत्री, पी. चिदम्बरम का भाषण, 8 जुलाई, 2004

भाग-क

अध्यक्ष महोदय,

I. प्रस्तावना

1. मैं वर्ष 2004-05 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
2. प्रत्येक पांच वर्ष में, अथवा कभी-कभी इससे भी पहले भारत की जनता अपनी सामूहिक आवाज में बोलती है। सामान्यतः यह संदेश असंदिग्ध और स्पष्ट होता है। वर्ष 2004 के चुनाव भी ऐसे ही थे। यह जनादेश एक गठबंधन के विरुद्ध था और दूसरे गठबंधन के पक्ष में था और यह परिवर्तन का जनादेश था। जैसा कि प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दो सप्ताह पहले राष्ट्र को अपने संबोधन में कहा था, जनता ने एक ऐसा परिवर्तन चाहा है “जिसमें देश को चलाया जाए, यह परिवर्तन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए है, और यह परिवर्तन शासन की प्रक्रियाओं और उसके मुख्य लक्ष्यों के लिए है।” मैं इस जनादेश के अनुरूप हर संभव प्रयत्न करूंगा।

II. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम : एक पथ प्रदर्शक

3. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने स्वयं को तथा इस देश की जनता को एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम दिया है। सरकार ने इसे अब एक राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के रूप में अंगीकार किया है। यह कार्यक्रम सात स्पष्ट आर्थिक उद्देश्यों का उल्लेख करता है :

- (1) निरंतर अवधि के लिए प्रतिवर्ष 7-8 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखना,
- (2) गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सर्वसुलभ बनाना,
- (3) कृषि, विनिर्माण एवं सेवाओं में लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना और निवेश को बढ़ावा देना,
- (4) प्रत्येक परिवार में न्यूनतम दर पर आजीविका कमाने वाले को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना,

- (5) कृषि एवं आधारभूत सुविधाओं पर जोर देना,
- (6) राजकोषीय मजबूती और सुधार में तेजी लाना, और
- (7) उच्चतर और अधिक कारगर राजकोषीय हस्तान्तरण सुनिश्चित करना।

4. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इस वर्ष मई में अपनी यात्रा शुरू की। फिर भी, मैं देखता हूँ कि वर्ष के तीन महीने बीत चुके हैं और बजट पारित होने तथा वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने तक वर्ष का लगभग आधा हिस्सा बीत जाएगा। मेरे पूर्ववर्ती मंत्री द्वारा एक अंतरिम बजट भी पीछे प्रस्तुत किया गया है।

5. सरकार को अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, और यदि हम शीघ्र ऐसा कर सकें तब भी इस वर्ष के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हमारे पास केवल लगभग छः महीने होंगे। अतः हमने एक नई पद्धति अपनाने का निर्णय लिया है। योजना आयोग ने मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी है कि वह अपनी प्राथमिकताओं को पुनः स्पष्ट करें और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार अपने कार्यक्रमों को दुबारा तैयार करें। इससे व्यय के प्रत्येक शीर्ष के अधीन आबंटनों में कुछ परिवर्तन अवश्यम्भावी हैं। इसके अलावा नए कार्यक्रमों या स्कीमों को शुरू करना पड़ सकता है और पुरानों की पुनर्संरचना करनी पड़ेगी। इन परिस्थितियों में यह उचित समझा गया कि चालू कार्यक्रमों को तब तक चलने दिया जाए जब तक योजना आयोग एक व्यापक पुनरीक्षा पूरी नहीं कर लेता और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप व्यय प्रणाली तैयार नहीं करता। परन्तु एक बात स्पष्ट है। अंतरिम बजट में उपलब्ध कराए गए योजना संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। अतः अंतरिम बजट में प्रदान की गई 135,071 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के अलावा मैं 10,000 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस और कुछ अन्य अतिरिक्त आबंटनों से 2004-05 के बजट अनुमानों में कुल योजना व्यय बढ़कर 145,590 करोड़ रुपए हो जाएगा।

III. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एवं वृहद् आर्थिक पृष्ठभूमि

6. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 ने बजट प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बना दिया है। सरकार ने 5 जुलाई, 2004 से उक्त अधिनियम और नियमावली को अधिसूचित करके विवेकपूर्ण राजकोषीय एवं वित्तीय नीतियों की अपनी वचनबद्धता प्रदर्शित की है। बजट के साथ एक वृहद् आर्थिक संरचना विवरण, एक मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, और एक राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण सदन के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

7. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन मैं 2007-08 तक राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए बाध्य हूँ। तथापि, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह प्रस्तावित है कि हम 2008-09 तक ऐसा करें। मेरे विचार में इसके लिए 2008-09 अधिक विश्वसनीय आखिरी वर्ष है। यह वर्ष इस सरकार के कार्यकाल से भी मेल खाता है। अतः मैं वित्त विधेयक के माध्यम से इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को कार्यान्वित करने के प्रति कटिबद्ध हूँ। राजकोषीय घाटे की समाप्ति से राजकोषीय सक्षमता पर प्रतिकूल असर डाले बिना बढ़े हुए सार्वजनिक निवेश के लिए सकल घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत तक की राजकोषीय वृद्धि हो जाएगी।

8. आर्थिक आधारभूत स्थितियाँ सुदृढ़ जान पड़ती हैं और भुगतान संतुलन की स्थिति मजबूत है। यद्यपि मूल्यों पर अल्पावधि दबाव है तो भी वर्ष की संभावनाएं अनुकूल हैं और सरकार पूरी

तरह सचेत है। कृषि में बढ़े हुए उत्पादन और मूल्य वर्धन, औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार और सेवा क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में निरंतर उछाल से वृद्धि बनाए रखी जाएगी।

9. सरकार स्थिरता तथा साम्य के साथ तीव्र विकास हासिल करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक 5-वर्षीय कार्य-योजना पर अमल करेगी। उपायों का समुचित रूप से क्रमबद्धीकरण और तीव्र विकास के युग में सुधार प्रक्रिया को जारी रखना मुख्य चुनौतियां हैं। सरकार विकास, स्थिरता और साम्यता के तीन परस्पर सुदृढ़कारी उद्देश्यों के बीच एक उत्कृष्ट संतुलन बनाने के प्रति वचनबद्ध है।

IV. गरीबी और बेरोजगारी मिटाना

10. हमारी एक सबसे बड़ी सम्पदा हमारे मानव संसाधन, हमारे लोग हैं। लोगों को, विशेषकर गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य तक उनकी सार्वभौम पहुंच बनाकर समर्थ बनाने और लाभकर रोजगार के माध्यम से विकास प्रक्रिया में उनकी पूर्ण भागीदारी को सुगम बनाने से उनके कल्याण में वृद्धि होगी। इससे स्वयं विकास प्रक्रिया में मजबूती आएगी। यह लाभकारी कार्यक्रम सरकार की आर्थिक नीति का आधार है।

योजना की पुनर्संरचना

11. मेरे पास हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन का लाभ है। हमारी कार्ययोजना में गरीब का स्थान सर्वोपरि होगा- न केवल 10,000 करोड़ रुपये की सकल बजट सहायता की अतिरिक्त राशि पर जिसे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव आज मैं करता हूँ वरन उन समूची आयोजना निधियों पर भी जिन्हें योजना आयोग पुनःआवंटित करेगा।

12. गरीब लोग अपने बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा चाहते हैं। हम इसकी व्यवस्था करेंगे और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा कम से कम आठ साल तक विद्यालय में रहे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा जब विद्यालय में रहे तो वह भूखा न रहे। गरीबों को पेयजल चाहिए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बस्ती में पेयजल का एक निश्चित स्रोत हो। गरीब बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या, वाजिब मूल्यों पर दवाएं और उचित दूरी पर डाक्टर चाहते हैं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्राथमिक चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मानवीय और वित्तीय संसाधन हों। गरीब अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं; हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्चतर निवेशों के माध्यम से और लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

13. हालांकि योजना आयोग अंतिम आवंटन करेगा, मैं सदन को यह आश्वासन दूँ कि अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे कि काम के बदले अनाज, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन स्कीम, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, रेलवे आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, पेयजल, कृषि में निवेश, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण सुख सुविधाओं के प्रावधान, सड़कें तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी जाएगी और उनके लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

अन्त्योदय अन्न योजना

14. मैं अन्त्योदय अन्न योजना को जारी रखने और उसका विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय 1.5 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हैं। इन परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के अत्यधिक सब्सिडीयुक्त मूल्य पर प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। 2003-04 में स्कीम के अंतर्गत

20.76 लाख टन चावल और 17.48 लाख टन गेहूँ वितरित किया गया। चालू वर्ष में, मैं 2 करोड़ परिवारों को योजना में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है कि चावल और गेहूँ के उठाव में बढ़ोतरी होगी। इसके परिणामस्वरूप, अन्त्योदय अन्न योजना को लगभग 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस व्यय के लिए 25,800 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी के आवंटन में प्रावधान रखा गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

15. उचित मूल्य की दुकानें निर्धन वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। हम इस प्रणाली में मौजूदा कमजोरियों को दूर करेंगे तथा लोक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाएंगे। मैं कुछ देर बाद, इस विषय पर फिर से चर्चा करूंगा।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

16. निवेश तथा विकास से युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यद्यपि, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बेरोजगारी से निर्धन लोगों पर अत्यधिक बुरा प्रभाव न पड़े। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पर कार्य आरंभ किया जा चुका है। इसका उद्देश्य, प्रत्येक निर्धन परिवार के एक स्वस्थ व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। इस विधेयक के संदर्भ में महाराष्ट्र में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार सम्मानीय समीक्षकों द्वारा इंगित जोखिमों से बचने की तरफ भी ध्यान देगी। मेरे साथी, श्रम मंत्री जी, को आशा है कि वह इस विधेयक को शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत कर देंगे। इस नए कानून को अधिनियमित किए जाने तक, मेरा सर्वाधिक पिछड़े वर्गीकृत 150 जिलों, जिन्हें ऐसे कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है के रूप में पहचाना गया है, मैं एक नया काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है। विभिन्न स्कीमों के आवंटनों को एकत्रित करके काम के बदले अनाज कार्यक्रम को सहायता प्रदान की जाएगी। एसजीआरवाई, एसजीएसवाई, एसजेएसआरवाई, आरईजीपी तथा पीएमआरवाई के अंतर्गत कुल 6000 करोड़ रुपए से अधिक की पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं। ऐसे कार्य के लिए मांग के आधार पर चालू वर्ष के दौरान और अधिक निधियों का आवंटन किया जाएगा। मुझे आशा है कि अगले चार वर्षों के दौरान इन आवंटनों में काफी वृद्धि की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करते समय विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि धन और श्रम के व्यय के परिणामस्वरूप स्थायी तथा स्पष्ट परिसंपत्तियों का सृजन हो जिससे सारे समुदाय को लाभ पहुंचे।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

17. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण संबंधी विषय का मेरे हृदय में विशेष स्थान है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 1180 करोड़ रुपए (1137 करोड़ रुपए से बढ़ाकर) तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 1146 करोड़ रुपए (1087 करोड़ रुपए से बढ़ाकर) का आवंटन किया गया है। एसजीएसवाई, एसजीआरवाई तथा आईएवाई जैसी अन्य योजनागत स्कीमों के अंतर्गत भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए विशेष आरक्षण रखे गए हैं। इन आरक्षणों का विस्तार 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक है।

अल्पसंख्यक

18. अल्पसंख्यकों के कल्याण, विशेषरूप से उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसलिए, अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन रखा गया है।

स्वयं-सहायता समूह

19. सूक्ष्म वित्त संबंधी पहल, बैंकिंग प्रणाली को निर्धन लोगों तक पहुंचाने का किफायती माध्यम होती है। 1992 में आरंभ किया गया स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) - बैंक संपर्क कार्यक्रम एक लंबी दूरी तय कर चुका है। 31 मार्च, 2004 तक, बैंकों द्वारा वित्तपोषित 10.79 लाख स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से 1.67 करोड़ परिवारों ने लाभ उठाया। जबकि एसएचजी अवधारणा को सक्रियता से आगे बढ़ाया जाएगा, मेरा मानना है कि विकसित स्वयं-सहायता समूह अब ऐसी स्थिति में होंगे कि वे अब उपभोक्ता अथवा उत्पादन संबंधी ऋण से लघु उद्यम आरंभ करने के स्तर पर आ सकते हैं। नाबार्ड, सिडबी, बैंकों तथा अन्य एजेंसियों के लिए 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के लिए 5.85 लाख स्वयं-सहायता समूहों के साथ ऋण संपर्क बनाने का निश्चयात्मक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

V. महत्वपूर्ण क्षेत्र

20. इससे पहले कि मैं चिंता के ऐसे अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करूं जिन पर इस बजट का प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत कर दूँ:

- तीन वर्षों में कृषि संबंधी ऋण को दोगुना करना, सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करना तथा ग्रामीण अवसंरचना में निवेश करना;
- कृषि बीमा तथा मवेशी बीमा की व्यवस्था करना;
- कृषि उत्पाद बाजारों में सुधार लाना, तथा कृषि कारोबार को प्रोत्साहन प्रदान करना;
- सभी के लिए पेयजल;
- जल संचयन, जलसंभर विकास तथा लघु और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार करना;
- नए कार्यों के सृजन हेतु सार्वजनिक तथा निजी, घरेलू तथा विदेशी उद्योग में निवेश को बढ़ाना;
- लघु उद्योग को फलने-फूलने का अवसर प्रदान करने की संभावना का पता लगाना;
- सभी के लिए बिजली;
- दूरसंचार सुविधाओं तक सभी लोगों की पहुंच;
- गरीबों के लिए और अधिक आवास निर्माण;
- स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से चिकित्सा देखभाल तक पहुंच; और
- बचतों को प्रोत्साहन देना तथा वरिष्ठ नागरिकों की बचतों को सुरक्षा प्रदान करना।

21. मुझे विश्वास है कि विकास की कुंजी निवेश में निहित है, चाहे वह सार्वजनिक तथा निजी निवेश हो, घरेलू तथा विदेशी निवेश। इसलिए मेरी मंशा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से निवेश को बढ़ाना है। तथापि, राजकोषीय सूझबूझ तथा वित्तीय अनुशासन सर्वोपरि लक्ष्य बना रहेगा। मैं संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न क्षेत्रों की आत्मसात क्षमता को भी ध्यान में रखूंगा।

VI. शिक्षा तथा स्वास्थ्य**शिक्षा**

22. मेरी विभिन्न योजनाओं में, कोई मुद्दा इतना अधिक प्राथमिकता का नहीं है जितना कि सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सरकार को

शिक्षा उपकर लगाने हेतु आदेश दिया गया है। मैं 2 प्रतिशत का उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस नए उपकर से संपूर्ण वर्ष में लगभग 4000-5000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। उपकर के रूप में संग्रहित की गई इस संपूर्ण राशि को शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा जिसमें स्वाभाविक है कि पोषक पका मध्याह्न भोजन का प्रावधान भी शामिल होगा। यदि प्राथमिक शिक्षा तथा पोषक पके भोजन की योजना साथ-साथ चले तो मुझे विश्वास है कि भारत के गरीब बच्चों के लिए एक नए सवरे का आगमन होगा।

23. मैं देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चिन्तित हूँ। भले ही मुझे गलत समझा जाए, लेकिन मैं आईआईटी के बारे में नहीं बल्कि आईटीआई के संबंध में उल्लेख कर रहा हूँ। आईटीआई, दक्ष जनशक्ति के लिए प्रशिक्षण का आधार है। आईटीआई द्वारा प्रदान की गई दक्षता को उद्योग की प्रौद्योगिक मांगों के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए और ज्ञान की व्यापकता को विस्तारित करना चाहिए। हमारे तकनीशियनों का केवल एक ही मानदंड है - और वह है विश्व मानदंड। विश्व मानदंड के अनुरूप तकनीशियनों को तैयार करने के लिए, सरकार का केन्द्रीय क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 500 आईटीआई को प्रतिवर्ष 100 आईटीआई के हिसाब से उन्नयन करने संबंधी कार्यक्रम को संचालित करने का प्रस्ताव है। उपयुक्त आधारभूत ढांचा तथा उपस्करों की व्यवस्था की जाएगी, पाठ्यक्रम का उन्नयन किया जाएगा और नए व्यवसाय प्रारंभ किए जाएंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं वाणिज्य और उद्योग चैम्बर का सरकार को सहयोग प्रदान करने और स्कीम के निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी के मॉडल को तैयार करने के लिए स्वागत करता हूँ। आईटीआई का चयन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

24. अप्रैल, 2001 से शैक्षणिक ऋण योजना चालू है जिसके तहत देश में तथा विदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु क्रमशः 7.50 लाख रुपए तथा 15 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध है। संपार्श्विक ऋण की इस अपेक्षा को 4 लाख रुपए तक के ऋणों के संबंध में समाप्त कर दिया गया था। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि वाणिज्यिक बैंक अब 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की संपार्श्विक आवश्यकता को यदि विद्यार्थी की ओर से संतोषप्रद गारंटी प्रदान की जाती है, माफ करने पर सहमत हो गए हैं। इस प्रकार किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें आईआईटी, आईआईएम पाठ्यक्रम तथा मेडिकल कालेज भी शामिल हैं, मैं प्रवेश लेने वाला कोई छात्र धन की कमी की वजह से शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं रहेगा।

स्वास्थ्य

25. गरीबों को चिकित्सा देखभाल आसानी से उपलब्ध नहीं है। अभी प्रचलित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम (यूएचआईएस) गरीबों से इतर लोगों के पक्ष में बनाई गई है। इसके परिणामस्वरूप गरीबी की रेखा (बीपीएल) से नीचे केवल थोड़े से परिवार - वास्तव में मई, 2004 तक 11,408 - इसके अंतर्गत आते हैं। यद्यपि किशतें कम हैं परन्तु बीपीएल परिवार इन किशतों के भुगतान की अपनी असमर्थता के कारण इस स्कीम से बचते दिखाई देते हैं। अपनी इस वर्तमान संरचना में यह स्कीम चल सकने वाली नहीं है। अतः मैं स्कीम को पुनः तैयार करने और इसे गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों एवं परिवारों के लिए पूर्ण रूप से बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। लाभ में किसी कटौती के बिना संशोधित किशत व्यक्तियों के लिए 165 रुपए, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 248 रुपए और सात सदस्यीय परिवार के लिए 330 रुपए होगी। किशत में कटौती को पूरा करने के लिए मैं किशत (प्रीमियम) सब्सिडी वर्तमान 100 रुपए से बढ़ाकर व्यक्ति के लिए 200 रुपए, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 300 रुपए और सात सदस्यीय परिवार के लिए

400 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। पूरे वर्ष में राजकोष पर 40 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। यदि धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए तो बीमाशुदा व्यक्तियों की संख्या लगभग 10 लाख हो जाएगी।

26. उपर्युक्त के अलावा, मैं सरकारी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से एक नई सामूहिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके बीमाशुदा व्यक्ति स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और अन्य ऋण संबद्ध समूहों (सीएलजी) के सदस्य होंगे जो बैंकों या सहकारी संस्थाओं से ऋण लेते हैं। सामूहिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति किश्त 120 रुपए की होगी परन्तु बीमा कवर 10,000 रुपए की धनराशि का होगा।

27. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम तीव्रकृत एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की आवश्यकता पर भी उचित रूप से जोर देता है। एचआईवी/एड्स की वृद्धि शून्य स्तर पर लाने के लिए साहसिक एवं दृढ़-निश्चयात्मक प्रयत्नों की आवश्यकता होगी। इनमें अधिक प्रहरी स्थलों की स्थापना के जरिए उन्नत निगरानी और एचआईवी/एड्स की मानीटरिंग के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उपयोग, जन-जागरूकता अभियान, कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध को बढ़ावा देना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम तथा नष्ट की जाने वाली सुइयों (सिरिंजेज) का वितरण शामिल होगा। एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 259 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

VII. कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था

28. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के पांच उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विविधीकरण के माध्यम से कृषि विकास में तेजी लाना तथा एग्रो-प्रसंस्करण का विकास करना है। 24 जून, 2004 को अपने राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास हेतु एक 'नए उपाय' का आश्वासन दिया है। यह नया उपाय न केवल ग्रामीण विकास तथा कल्याण के लिए अनिवार्य है बल्कि 7-8 प्रतिशत की सतत समग्र वार्षिक विकास दर प्राप्त करने तथा रोजगार सृजन के लिए भी आवश्यक है।

29. कृषि क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। ऐसा निवेश ऋण सक्षम निजी निवेश तथा वर्धित सार्वजनिक निवेश के माध्यम से करना होगा। मेरी मंशा कृषि में निवेश को बढ़ाने हेतु राजकोषीय उपायों के प्रयोग करने की भी है।

ऋण

30. मेरी मंशा है कि तीन वर्षों में कृषि ऋण का प्रवाह दुगुना हो जाए। हमने 18 जून, 2004 को कृषि ऋण संबंधी व्यापक नीति की घोषणा कर इस दिशा में शुरुआत की है। इस नीति के संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और यदि आवश्यक हो तो इसे और व्यवस्थित रूप दिया जाएगा।

31. सरकार ने इस नीति के कार्यान्वयन का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को सौंपा है।

32. प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक प्रायोजक बैंक है। मेरा प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रायोजक बैंक अपने अधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य निष्पादन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो प्रशासन संबंधी नए मानदण्डों को अपनाएंगे तथा जो नीतिगत नियमों का पालन करेंगे, वे बैंक अपने पुनर्गठन के लिए सरकार से निधियां प्राप्त करने के पात्र होंगे।

33. कृषि संबंधी ऋण प्रदान करने का तीसरा माध्यम सहकारी बैंक प्रणाली है। जब तक सहकारी बैंक मजबूत और ऋण-देने योग्य नहीं होंगे तब तक ऋण के जरूरतमंद प्रत्येक किसान तक ऋण पहुंचाना संभव नहीं होगा। स्थिति बहुत गंभीर है। एक स्थायी हल निकालने की दृष्टि से, मैं एक कार्यबल नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ जो सहकारी बैंकिंग प्रणाली, जिसमें समुचित विनियामक तंत्र भी शामिल है, में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करेगा। इस कार्यबल से अनुरोध किया जाएगा कि वह बहुत तेजी से अपना कार्य करे तथा अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2004 तक प्रस्तुत कर दे।

सिंचाई, ग्रामीण अवसंरचना

34. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) को 1996-97 में आरम्भ किया गया था तथा वर्ष-दर-वर्ष इसे बड़े पैमाने पर निधियां प्रदान की गईं। फिर भी 178 बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिनकी पहचान की गई थी, में से केवल 28 परियोजनाएं ही पूरी हो पाई हैं। इस कार्यक्रम को फिर से तैयार किया जा रहा है। समाप्ति के कगार पर ऐसी परियोजनाओं, जो मार्च, 2005 तक पूरी हो जाएंगी, को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी तथा ऐसी अन्य परियोजनाओं, जिन्हें मार्च, 2006 तक पूरा किया जा सकता है, को भी चालू वर्ष में शामिल कर लिया जाएगा। अगले वर्ष, हम इस लक्ष्य को बढ़ा कर मार्च, 2007 कर देंगे, उससे अगले वर्ष उस लक्ष्य को मार्च, 2008 कर देंगे तथा इसी प्रकार यह आगे बढ़ता जाएगा। मैंने इस वर्ष इस कार्यक्रम के लिए 2800 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है।

35. ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना नाबार्ड में 1994-95 में की गई थी। पांच महीने पहले आरआईडीएफ को बंद करके कुछ अलग उद्देश्य वाली एक अन्य निधि की स्थापना की गई। कुछ राज्य सरकारों तथा बहुत से माननीय सदस्यों ने आरआईडीएफ को बंद करने का विरोध किया था। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए तथा मेरी अपनी सोच के अनुसार, मैंने आरआईडीएफ को फिर से आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इस निधि के मार्गनिर्देशों को संशोधित किया गया है तथा 2004-05 के दौरान आरआईडीएफ के लिए 8000 करोड़ रुपये की आधारभूत निधि प्रदान की जाएगी।

जल निकायों की पुनः स्थापना

36. अब मैं अपने एक बड़े स्वप्न की चर्चा करता हूँ। जल किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा होता है। हमें चेतावनी दी गई है कि 21वीं शताब्दी में विश्व को जिस सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा वह जल का संकट होगा। जल वास्तव में एक नवीकरणीय संसाधन है लेकिन किसी भी वर्ष में यह अक्षय नहीं हो सकता। जल के संकट से हमारे लाखों साथी नागरिकों के जीवन प्रभावित हुए हैं। कुछ शहरों में, आधी रात के बाद पूरे परिवार एक या दो बाल्टी पानी की प्राप्ति के लिए जागते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, पानी भरने के लिए अक्सर बालिकाओं को स्कूल से निकाल लिया जाता है। मैं इस आसन्न संकट से पूरी तरह चिंतित हूँ। इसलिए मैं एक महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव रखता हूँ। युगों-युगों से, भारतीय कृषि झील, तालाब जैसे प्राकृतिक तथा मानव निर्मित जल निकायों पर आश्रित रही है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक मिलियन से भी अधिक ऐसी संरचनाएं हैं तथा लगभग 500,000 का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। उनमें से बहुत सी संरचनाओं का उपयोग नहीं किया जाता। बहुत सी संरचनाओं में गाद भर गई है और कई संरचनाओं की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है।

37. इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कृषि से जुड़े सभी जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनः स्थापना के लिए एक बड़ी योजना आरम्भ की जाए। चालू वर्ष के दौरान, हम कम से कम पांच

जिलों में प्रायोगिक योजनाओं से शुरुआत करेंगे तथा हम देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में कम से कम एक जिले का चयन करेंगे। इसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए है। इन पांच प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए एसजीआरवाई, पीएमजीएसवाई, डीपीएपी, डीडीपी तथा आईडब्ल्यूडीपी जैसे मौजूदा कार्यक्रमों से निधियों को निकाला जाएगा। एक बार प्रायोगिक परियोजनाओं के पूरा हो जाने तथा प्रामाणिक हो जाने के पश्चात्, सरकार राष्ट्रीय जल संसाधन विकास परियोजना को आरम्भ कर देगी तथा 7 से 10 वर्ष की अवधि में इसे पूरा कर लेगी।

38. इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों से संबंधित कोई बाधा नहीं आएगी। उदाहरण के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम प्रत्येक वर्ष औसत 3000 करोड़ रुपए की राशि जल संबंधी कार्यक्रमों में निवेश करता है। मेरा इरादा, निधिकरण के लिए इस परियोजना को बहुपक्षीय एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करने का भी है। मुझे आशा है कि आगामी दशक के प्रारम्भ होने तक भारत के सभी जल निकायों को उनकी मूल गरिमा के साथ पुनःस्थापित कर दिया जाएगा तथा इन जल निकायों की भंडारण क्षमता को कम से कम 100 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा।

जल संचयन

39. किसी क्षेत्र या गांव के लिए विशिष्ट जल संचयन योजनाएं अत्यधिक उपयोगी पाई गई हैं। ये योजनाएं अनेक ऋण संस्थाओं द्वारा समर्थित होती हैं। तथापि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ऐसी योजनाओं का लाभ विरले ही मिलता है। इन किसानों की मदद करने के उद्देश्य से सरकार एक राष्ट्रव्यापी जल संचयन योजना शुरू करेगी। इस योजना में प्रति यूनिट 20,000 रुपए की औसत लागत पर एक लाख सिंचाई यूनिटें शामिल की जाएंगी नाबार्ड आसान शर्तों पर ऋण देगा और उधारकर्ता से कोई मार्जिन राशि प्रभारित नहीं की जाएगी, सरकार नाबार्ड के माध्यम से 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी और योजना के लिए अनुमान 100 करोड़ रुपए है।

बाढ़ नियंत्रण

40. प्रति वर्ष बाढ़ के कारण हजारों की संख्या में व्यक्तियों व पशुओं की जानें जाती हैं। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ का प्रकोप होता है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अन्तर्राज्यीय नदियों और अन्तर्राष्ट्रीय नदियों पर बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए पूर्ण केन्द्रीय सहायता परिकल्पित है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में भूक्षरण-रोधी और बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए एक योजना तैयार की है। बाढ़ नियन्त्रण और भूक्षरण-रोधी कार्यक्रम चालू वर्ष में शुरू किया जाएगा। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के गंगा-बेसिन में इसी तरह का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। चालू वर्ष में 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और कार्य की प्रगति के अनुसार अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

विविधीकरण

41. भारत गेहूं और धान में आत्म निर्भर है परन्तु अन्य कृषि उपजों में कमी है। समय आ गया है कि हमारे किसानों को बागवानी, फूलों की और तिलहनों की खेती जैसे क्षेत्रों को अपनाकर कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूध और दुग्ध उत्पादों में आनंद माडल बहुत अधिक सफल रहा है, सरकार का एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य बागवानी उत्पादन को 150 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से दुगुना करके 2011-12 तक 300 मिलियन टन करना है। मैं इस मिशन की शुरुआत करने में सरकार के साथ हाथ मिलाने के

लिए राज्यों को आमंत्रित करता हूँ। राज्यों को, आनंद माडल का अनुकरण करने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय सहकारी समिति की स्थापना करने जैसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

42. तिलहन एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गत वर्ष हमने 25 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन किया परन्तु हमने 2.5 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का खाद्य तेल का आयात भी किया। सरकार उत्तम कोटि की बीज-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर और मूल्य समर्थन की उपयुक्त नीति के माध्यम से किसानों के लिए तिलहन की खेती करना सुविधाजनक बनाएगी।

43. भारत को सभी उत्पादों, विशेषकर कृषि उपजों के लिए एक एकल बाजार बनना चाहिए। कृषि उत्पाद विपणन समितियों को शासित करने वाले मौजूदा कानूनों की उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है। सरकार ने एक मॉडल कानून परिचालित किया है। अब तक दस राज्यों ने मॉडल कानून की तर्ज पर 'प्रत्यक्ष विपणन' और 'संविदा कृषि' के लिए वैधानिक या प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की है। मैं सभी राज्यों से यथाशीघ्र मॉडल कानून बनाने का आग्रह करता हूँ।

अनुसंधान और विकास

44. कृषि अनुसंधान और विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एक ऐसी योजना का लाभार्थी है जिसके अंतर्गत आईसीएआर द्वारा अर्जित प्रत्येक वाणिज्यिक रुपए के बराबर, वर्धित रुप से बजट से एक और रुपया उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त आईसीएआर को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में जो वाणिज्यिक रुप से सक्षम हैं, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से निधियां प्राप्त होती हैं। कृषि अनुसंधान का तेजी से जैव-प्रौद्योगिकी, वैक्सीन और निदान शास्त्र जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए। शुष्क भूमियां और असंचित क्षेत्रों में खेती पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। 2004-05 के लिए आवंटन 1000 करोड़ रुपए है (जिसमें बजट अनुमान 2003-04 में 775 करोड़ रुपए से वृद्धि की गई है) और मैं वर्ष के दौरान और अधिक आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

कृषि कारोबार

45. वर्ष 1994 में लघु कृषक कृषि कारोबार सहायता संघ (एसएफएसी) की स्थापना हुई थी। यद्यपि एसएफएसी ने वर्ष 1998 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था, लेकिन इसकी आधारभूत निधि में 10.95 करोड़ रुपए की स्वल्प राशि थी। मेरी दृष्टि में, एसएफएसी को परियोजनाओं के संचालन हेतु-जोखिम पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए और पूर्णतया कारोबार की तर्ज पर तरज़ीही तौर पर किसी बैंकर द्वारा इस सहायता संघ का संचालन किया जाना चाहिए। एमएस स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन ने ऐसे 13 जिलों की पहचान की है जहां कृषि-कारोबार की भारी सम्भावना है और लगभग 170 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। कृषि मंत्रालय ने एसएफएसी की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की है जिसमें मुख्य कार्यपालक के तौर पर बैंकर की नियुक्ति करना भी शामिल है। मैं अपनी ओर से एसएफएसी को आवश्यक अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ जिसकी-आवश्यकता उसे कृषि-कारोबार को तेजी से प्रोत्साहित करने हेतु है।

जोखिम कम करना

46. कृषि बीमा कम्पनी (एआईसी) को दिसम्बर, 2002 में निगमित किया गया था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) जो उपज अथवा फसल का बीमा करती है, रबी 1999-2000 से

प्रचालन में है। एआईसी योजना को नए सिरे से तैयार कर रही है। हम स्कीम से जुड़े रहेंगे तथा एक अन्य मूल्यांकन करेंगे। इस बीच, रबी 2003-04 के दौरान 12 राज्यों के 19 जिलों में कृषि आय (फसल के बजाए) के बीमा की एक प्रायोगिक-योजना प्रारम्भ की गयी है। सरकार ने इसकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने हेतु इस योजना को खरीफ 2004 में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि मौसम बीमा योजना, कम से कम डिजाइन में, अपेक्षाकृत अधिक सम्भावना पूर्ण प्रतीत होती है। एआईसी चालू फसल मौसम में 20 वर्षा मापक केन्द्रों में प्रायोगिक आधार पर इस योजना को प्रारम्भ कर रहा है। इस चरण में यह कहना कठिन होगा कि तीन योजनाओं में कौन सी योजना सफल होगी। कृषि बीमा तथा मवेशी बीमा जटिल उत्पाद हैं तथा इन्हें सावधानी से तैयार करना होगा। मैं कृषि तथा मवेशी को बीमा कवर उपलब्ध कराने की सरकार की वचनबद्धता को पुनः दोहराता हूँ।

VIII. आधारभूत ढांचा

47. निरन्तर विकास की प्रक्रिया कारगर आधारभूत ढांचे की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सरकार नीति तथा राजकोषीय उपायों के संयोजन से ढांचागत सुविधाओं की अपर्याप्तताओं को दूर करने हेतु वचनबद्ध है।

अंतर-सांस्थानिक समूह

48. विद्युत क्षेत्रक में एक अंतर-स्थानिक समूह 6 विद्युत परियोजनाओं का वित्तीय-समापन करने में सफल हो गया है। अन्य 10 परियोजनाएं वित्तीय-समापन प्राप्त करने के कगार पर हैं। इस अवधारणा का विस्तार कुछ अन्य आधारभूत सुविधा क्षेत्रकों में किया जा सकता है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आईडीबीआई., आईडीएफसी., आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई., एलआईसी., बैंक आफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक ने एक अंतर-सांस्थानिक समूह (आईआईजी) का गठन कर लिया है। वह अपने संसाधनों को तुरंत आधार पर 'पूल' करेंगे और जब भी आवश्यक होगा, 40,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। आईआईजी ऋण करारों का शीघ्र निष्पादन और आधारभूत सुविधा परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। प्रारंभ में विमानपत्तन, बन्दरगाह और पर्यटन आईआईजी के लक्ष्य-क्षेत्रक होंगे।

जल-आपूर्ति

49. राजीव गांधी पेयजल मिशन को 'मिशन मोड' के रूप में कार्यान्वित करने का इरादा था। परन्तु हाल के वर्षों में नये कार्यक्रम उभर कर आये हैं और मूल मिशन को भुला दिया गया है। 75,000 से अधिक निवासों को अभी भी पर्याप्त पेय जल उपलब्ध कराया जाना है। सरकार का इरादा सभी पेयजल स्कीमों को राजीव गांधी पेयजल मिशन के संरक्षण में लाना है।

50. त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) को चालू वर्ष में 2610 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। यह जल संसाधनों के नवीकरण और शामिल न किये गये तथा आंशिक रूप से शामिल किये गये निवासों को सुविधा प्रदान करने पर केन्द्रित होगा। पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकारों के परामर्श से ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, स्वामित्व रखने, संचालन और अनुसंधान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को एआरडब्ल्यूएसपी के कार्यान्वयन के लिये निधियों की सुपुर्दगी की जाएगी।

51. इसी तरह शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में चल रहा है। 2151 नगर इस कार्यक्रम के अधीन विचारार्थ हैं। चालू वर्ष में 151.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

52. चैन्नई नगर तथा अन्य बहुत से नगरों में पेयजल का अत्यधिक संकट है। चैन्नई के निकट, राज्य क्षेत्र में, पहला विशाल विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा कोरोमंडल तट पर ऐसे और भी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 300 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र पर 1000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है तथा पारेषण पाइपलाइनों और सीमित विद्युत संयंत्र के लिए अल्प लागत भी आएगी। प्रस्ताव है कि इस परियोजना को सरकारी-निजी भागीदारी द्वारा कार्यान्वित किया जाए।

सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजना

53. सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजना भारतीय प्रायद्वीपीय लोगों का सपना नहीं बल्कि बहुप्रतीक्षित मांग है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर, द्वारा इस परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को पूरा कर लिया गया है। यह संस्थान अब तकनीकी-आर्थिक एवं इंजीनियरिंग व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है तथा इस रिपोर्ट को शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है। नौवहन मंत्रालय का एक विशेष प्रयोजनी साधन (एसपीवी) आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस एसपीवी के द्वारा इस परियोजना के लिए धनराशि जुटाई जाएगी तथा इक्विटी सहायता और ऋण-गारंटी के संयोजन के माध्यम से सरकार इस के निधिकरण में योगदान करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतांतरण टर्मिनल (आईसीटीटी), वल्लारपदम

54. सरकार द्वारा पत्तन अवसंरचना के विकास और विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान में, अपर्याप्त ड्राफ्ट और कार्गो संचालन अवसंरचना के कारण तथा आंशिक रूप से स्थान संबंधी असुविधाओं के कारण, मुख्य मार्गों पर चलने वाले जलयान अक्सर भारतीय पत्तनों पर आने से बचते हैं। भारत से कंटेनरों को पहले कोलंबो तक पोतांतरित किया जाता है और वहां से उन्हें अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। अन्य प्रमुख भारतीय पत्तनों की तुलना में कोची को स्थान संबंधी लाभ प्राप्त है क्योंकि यह प्रमुख समुद्री मार्गों के अधिक नजदीक है। सरकार द्वारा कोची पत्तन में वल्लारपदम स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतांतरण टर्मिनल की निर्माण सुविधा 'बनाओ, परिचालन करो तथा अंतरित करो' (बीओटी) आधार पर प्रदान की जाएगी।

ग्रामीण आवास

55. इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) ग्रामीण गरीब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ ही गैर-अनुसूचित जाति/जनजातियों हेतु आवास निर्माण का एक मुख्य माध्यम रही है। आईएवाई के अधीन निर्मित मकान ग्रामीण परिवारों हेतु ऋण तथा सब्सिडी योजना के अधीन बनाए जाते हैं। पात्र परिवारों को 10,000 रुपये तक की सब्सिडी तथा 40,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ब.अ. 2003-04 में आईएवाई के लिए आवंटन 1710 करोड़ रुपये था। चालू वर्ष में, मैं इस आवंटन को 2247 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। यदि और धन की आवश्यकता होगी तो इस वर्धित-आयोजना परियोजना के अन्तर्गत पूरा किया जाएगा।

56. आईएवाई को सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास निर्माण वित्त योजना अगस्त, 1997 में प्रारम्भ की गयी थी। इसकी प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है और अब तक 10.26 लाख आवास इकाइयां वित्तपोषित हो गयी हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 180,000 आवास इकाइयों पर ही इसका स्थिर रहना प्रतीत होता है। इस योजना को और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मुझे यह घोषणा करने में

प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय आवास बैंक ने इस वर्ष 25 आधार-बिन्दुओं द्वारा पुनर्वित्तपोषण की दर को घटाने की पेशकश की है। भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण आवास निर्माण हेतु बैंकों द्वारा ऋण की वापसी अदायगी के मानदंडों को संशोधित करने हेतु सहमत हो गया है ताकि किशतों का मेल फसल चक्रों से हो। ग्रामीण आवासन के लिए ऋण प्रदान करने में सबसे बड़ी बाधा जोत के सम्बन्ध में उपयुक्त मालिकाना हक का न होना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिभूति के सृजन को सरल रूप देने के लिए कानून बनाया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कानून का अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा किया जाए। इन परिवर्तनों के साथ, मुझे विश्वास है कि प्रतिवर्ष 250,000 ग्रामीण आवासन इकाइयों के उच्च लक्ष्य को निर्धारित करना सम्भव हो जाएगा।

IX. उद्योग

57. भारत में निवेशकों के लिए आकर्षक माहौल पैदा करना मेरा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मैं एक निवेश आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस आयोग को भारत में निवेश करने हेतु घरेलू तथा विदेशी कारोबारियों को आकर्षित करने, उनसे वार्तालाप करने तथा उन्हें आमंत्रित करने के सम्बन्ध में सरकार की ओर से व्यापक प्राधिकार प्राप्त होगा। इस आयोग की अध्यक्षता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने एक उपयोगी भूमिका निभाई है और अभी भी यह प्रस्तावित निवेश के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सहमति प्राप्त करने के लिए एक-स्थानिक केन्द्र (वन-स्टॉप सेंटर) के रूप में कार्य करता है। सरकार का विश्वास है कि एफआईपीबी के अनेक कार्यों को ऑटोमेटिक रूट पर रखा जा सकता है और एफआईपीबी को एक एकल-स्थानिक सेवा केन्द्र और सुविधा केन्द्र के रूप में बदला जा सकता है। घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का कार्य प्रस्तावित निवेश आयोग द्वारा किया जाएगा।

58. सरकार का एक राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव है। यह परिषद विनिर्माण उद्योगों की अभिवृद्धि को उर्जित करने और उसमें निरन्तरता लाने हेतु नीतिगत विचार-विमर्श का एक सतत मंच होगी। परिषद से विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने को कहा जाएगा। परिषद प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि के लिए उद्योग अथवा क्षेत्रक-विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफारिश भी करेगी।

59. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ जुड़ने की सम्भाव्यता है। राष्ट्रीय साझा-न्यूनतम कार्यक्रम में यह घोषणा की गई है कि विशेषकर बुनियादी ढांचा, उच्च प्रौद्योगिकी और निर्यात के क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित और सक्रिय रूप से आकर्षित किया जाता रहेगा। अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक इस कसीटी पर खरे उतरते हैं। ये हैं दूर संचार, नागरिक उड्डयन और बीमा। इन क्षेत्रकों में विशाल मात्रा में पूंजी का निवेश करने की तात्कालिक आवश्यकता है। अतः मैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्रकवार अधिकतम सीमा बढ़ाकर दूर-संचार में 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत; नागरिक उड्डयन में 40 प्रतिशत से 49 प्रतिशत; और बीमा में 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

पूंजी बाजार

60. सरकार पूंजी बाजारों के व्यवस्थित विकास और कामकाज के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजी बाजारों को व्यापक बनाने तथा विनियामक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। ऐसे कुछ संकेत हैं कि खुदरा निवेशक पूंजी बाजार में लौट रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अन्य उभरते हुए बाजारों की तुलना में भारत के प्रति सुस्पष्ट तरजीह दर्शाई है।

भारतीय पूंजी बाजार को सुदृढ़ और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिये मैं यह प्रस्ताव करता हूँ:-

- * विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिये पंजीकरण और प्रचालन प्रक्रियाओं को सरलतर और शीघ्रतर बनाना;
- * ऋण निधियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिये निवेश की अधिकतम सीमा 1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1.75 बिलियन अमरीकी डालर करना।
- * बैंकों को पूंजी बाजार में अपने ऋण जोखिम में सशक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के साथ अधिक छूट देना।
- * पूंजी बाजार से इक्विटी और ऋण जुटाने के लिये छोटे और मझोले उद्यमों (एस.एम.ई.) हेतु एक वैकल्पिक व्यापार प्लेटफार्म बनाना; और
- * वस्तु बाजारों और प्रतिभूति बाजारों के एकीकरण के लिये कदम उठाना।

इन मामलों के संबंध में आर.बी.आई. और 'सेबी' आवश्यक उपायों की घोषणा करेंगे। मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी है कि 'सेबी' दीर्घकाल से चले आ रहे दलालों के शुल्क के मुद्दे को हल करने में सफल रहा है और दलाल इस बारे में शीघ्र एक घोषणा की आशा कर सकते हैं।

61. अनेक असली विदेशी सांस्थानिक निवेशक परिसंपत्ति प्रबन्धकों और वित्तीय विश्लेषकों के व्यावसायिक निकाय हैं जो इक्विटी पूंजी प्रवाह बढ़ा सकते हैं और पूंजी-बाजारों को व्यापकता प्रदान कर सकते हैं। एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने कतिपय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विदेशी संस्थागत निवेशों की सीमाओं के उदारीकरण की सिफारिश की है। मैं संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से इन सिफारिशों की जांच एवं कार्यान्वयन का प्रस्ताव करता हूँ।

सरकारी क्षेत्रक

62. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सरकार की नीति की घोषणा की गई है। हालांकि, रुग्ण सरकारी उपक्रमों के कारण बहस तो बहुत हुई है लेकिन जिन सरकारी उपक्रमों की हालत अच्छी है, उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार 2004-05 के दौरान केन्द्र सरकार के उपक्रमों (रेलवे सहित) को 14,194 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता तथा 2132 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करेगी। मुख्य निवेश विद्युत, दूरसंचार, रेलवे, सड़कों, पेट्रोलियम, कोयला तथा नागर विमानन से जुड़े सरकारी उपक्रमों में किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्यरत सुदृढ़ तथा प्रभावी सरकारी क्षेत्र के संबंध में सरकार की गहन वचनवद्धता की प्रशंसा करेंगे।

63. निश्चय ही सरकारी क्षेत्र का एक दूसरा पहलू भी है। इस पहलू में समस्याओं का घेरा है तथा हम इन समस्याओं को जिम्मेदारी और साहस के साथ दूर करेंगे। विनिवेश तथा निजीकरण उपयोगी आर्थिक साधन हैं। हम अपनी घोषित नीति के अनुरूप विशिष्टता से इन साधनों का प्रयोग करेंगे। पहले कदम के रूप में, मैं सरकारी क्षेत्र उपक्रम पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह बोर्ड सरकार को सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन हेतु किए जाने वाले उपायों, जिनमें विनिवेश अथवा समापन अथवा बिक्री को न्यायसंगत ठहराया जाता है, जैसे मामले भी शामिल होंगे, के बारे में सरकार को परामर्श देगा।

64. हमारी नवरत्न कंपनियों में एक राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से पूंजी जुटाने हेतु सेबी के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया है। इसके परिणामस्वरूप

एन.टी.पी.सी में सरकार की धारिता कुछ कम हो जाएगी। अपनी धारिता का मूल्य प्राप्त करने तथा उक्त कमी को पूरा करने के लिए सरकार का इरादा एन.टी.पी.सी के सार्वजनिक निर्गम के संबंध में आवश्यक साथ-साथ सहायता करने तथा अपनी धारिता के लगभग पांच प्रतिशत भाग का विनिवेश करने का है। इस तथा कुछ अन्य मामलों, जो अभी विचाराधीन हैं, से चालू वर्ष के दौरान 4000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। जबकि ये विनिवेश-राजस्व भारत की समेकित निधि का हिस्सा होंगे, 2005-06 का बजट प्रस्तुत करते समय मैं सदन को इस बात की सूचना दूंगा कि उपरोक्त राजस्व का निर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में किस प्रकार उपयोग किया गया है अथवा किया जाएगा।

65. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के संबंध में राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में स्पष्ट नीतिगत मार्ग निर्देश सन्निहित हैं। सरकार जब तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर नियंत्रण रखती है तथा इसका सार्वजनिक क्षेत्र का चरित्र प्रभावित नहीं होता हो तो सरकार अपनी इक्विटी कम कर सकती है और लोगों की सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संसाधन जुटा सकती है। मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण बोर्ड से यह कहने का प्रस्ताव करता हूँ कि वह प्रत्येक मामले की यथार्थ में जांच करे और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप विनिवेश सिफारिशें करे।

66. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने पुनःसंरचना के कार्य को पूर्ण गंभीरता से लिया है। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की पुनःसंरचना हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। भारतीय टेलीफोन उद्योग (आई.टी.आई.) के लिए एक बचाव पैकेज तैयार किया गया है तथा आई.टी.आई. को बी.आई.एफ.आर. के जाल से बाहर रखने के लिए 508 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

लघु उद्योग

67. लघु उद्योग अभिवृद्धि का साधन है और इसे माना भी जाना चाहिए। इसी के साथ लघु उद्योगों की इकाइयों को मध्यम उद्यमों के रूप में बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। लघु और मध्यम उद्यमों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पूरे विश्व में नीतियां बनाई गई हैं। इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग मंत्रालय ने 85 मदों की पहचान की है जिन्हें आरक्षित सूची से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सकता है। इससे भी बढ़कर, यह महसूस किया गया है कि लघु उद्योग इकाइयों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में व्यवसाय करने की अत्यावश्यक जरूरत है। मैंने पूंजी सब्सिडी योजना की पुनरीक्षा की है और मैं इस योजना के अन्तर्गत उच्चतम सीमा 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। सब्सिडी की दर भी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जाएगी। इस योजना में और उप-क्षेत्रों तथा सहायता के लिए पात्र प्रौद्योगिकियों को जोड़कर इसके क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। लघु उद्योग इकाइयों को क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुझे आशा है कि इन उपायों से अनेकानेक लघु उद्योग इकाइयां इस पुनःसंरचित योजना से लाभ उठाएंगी। 'लघु उद्योग योजना को बढ़ावा' देने के लिए 135.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उस राशि के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी योजना हेतु निधियां मिल सकेंगी।

परम्परागत उद्योगों का पुनरुद्धार

68. हमारे कुछ परंपरागत उद्योग नामतः नारियल जटा, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन बनाने और अन्य कुटीर उद्योगों में अभिवृद्धि व निर्यात की विपुल संभाव्यता ही नहीं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं।

तदनुसार, परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु 100 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन के साथ एक निधि की स्थापना की जाएगी। इस निधि के उपयोग के लिए तंत्र सहित ब्यौरे संबंधित उद्योगों के साथ परामर्श से तैयार किए जाएंगे।

X. अन्य प्रस्ताव

वैट

69. मूल्य वर्धित कर एक ऐसा कर है जिसका परीक्षण जांच हुई है तथा पूरे विश्व में इसे लाभप्रद पाया गया है। अपने देश को एक आधुनिक तथा सक्षम व्यापार कर प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं को शामिल किया गया हो। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की 18 जून, 2004 को हुई बैठक, जिसमें सभी वित्त मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था और इसकी अध्यक्षता मेरे अनन्य मित्र डा. असीम दास गुप्ता ने की थी, में वैट लागू करने की राज्यों में मोटे तौर पर सहमति थी। इसके कार्यान्वयन हेतु 1 अप्रैल, 2005 की तारीख निर्धारित की गई है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ व राज्य सरकारों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सभी राज्यों से अनुरोध करता हूँ कि जिन्होंने अभी संगत वैट विधान पारित नहीं किया है उसे 2004 के अन्त तक पारित कर लें। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ ही हरियाणा का अनुभव यह संकेत देता है कि वैट से राजस्व में वृद्धि होगी, इससे राजस्व में हानि नहीं होगी। तो भी राज्यों को सुखद स्थिति में रखने के लिए राजस्व की हानि, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु एक सूत्र तैयार करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैंने राज्यों को एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सेवाओं की पेशकश की है। यह समिति निकटता से राज्यों के साथ काम करेगी और स्थिर रूप से क्रियान्वयन के चरण की तरफ जाने में उनकी मदद करेगी।

पेंशन सुधार

70. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये 1 जनवरी, 2004 से, जो उस तारीख में या उसके बाद भर्ती किये गये हैं, एक 'परिभाषित अंशदान' पेंशन स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के लिये एक विनियामक ढांचा प्रदान करने हेतु एक उचित कानून संसद में पेश किया जाएगा।

निर्यात-संवर्धन

71. मेरे साथी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री इस महीने के अंत तक संसद के समक्ष एक नई व्यापार नीति पेश करेंगे। सरकार का यह विचार है कि विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) विकास के इंजन हैं जो विनिर्माण, निर्यातों एवं रोजगार में तेजी ला सकते हैं। निजी क्षेत्रक ने एस.ई.जेड. के विकास में काफी रूचि दिखाई है। पांच एस.ई.जेड. ने कार्य शुरू कर दिया है। एस.ई.जेड. के लिये एक विशेष राजकोषीय एवं विनियामक तंत्र की आवश्यकता है। वाणिज्य मंत्री विशेष आर्थिक जोन्स के विनियमन के लिये शीघ्र ही एक विधेयक पेश करेंगे और मेरा विश्वास है कि ऐसा कानून पारित करना विनिर्माण एवं निर्यातों का एक बड़ा केन्द्र बनने की हमारी अभिलाषा में एक कीर्तिमान साबित होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम

72. वित्तीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों की संवैधानिक वैधता को, धारा 17 की उपधारा (2) को छोड़कर, उच्चतम न्यायालय द्वारा बहाल किया गया है। इस फैसले के अनुसरण में अनेक बैंकों ने अनिष्पादनकारी परिसंपत्तियों की वसूली को तेज करने में संभावित रूप से उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उधारकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार के बारे में उच्चतम न्यायालय की धिन्ता

उचित रूप से दूर करने और साथ ही साथ वसूली प्रक्रिया विलम्बित और बाधित न हो यह सुनिश्चित करने के लिये अधिनियम के संगत उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है। बैंकों को देय ऋणों की वसूली और वित्तीय संस्था अधिनियम, 1993 में, यदि आवश्यक हुआ, संबंधित संशोधन भी किये जायेंगे।

ब्याज दरें

73. केन्द्र सरकार ने कम ब्याज दरों के कारण नये उधारों पर ब्याज के मामले में काफी बचत की है। राज्य निम्न ब्याज दरों पर उधार लेने और पुराने उच्च लागत के ऋणों की अदला-बदली करने में भी समर्थ थे। 2002 से राज्यों को ऋण अदला-बदली योजना के माध्यम से लगभग 2500 करोड़ रुपए तक का लाभ पहुंचा है। उधारकर्ताओं को जहां साधारण ब्याज दरों का लाभ मिला है, वहीं बचतों को बढ़ावा देने और बचतकर्ताओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि देश के व्यापक हित में हमें एक हितकर ब्याज दर व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए जो बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के विधिसम्मत दावों में उपयुक्त सन्तुलन बनाए रखे।

74. मेरा विश्वास है कि सभी ब्याज दरों को, एकाध अपवादों को छोड़कर, बाजार से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। एक ऐसी बचत योजना की आवश्यकता है जो वयोवृद्ध नागरिकों को बाजार-निर्धारित दर से अधिक प्रतिफल प्रदान करे। एक ऐसे बचत प्रपत्र की भी आवश्यकता है जो सभी नागरिकों को अधिक लम्बी अवधि के लिए बचत का एक जोखिम रहित अवसर प्रदान करे और इस प्रकार के प्रपत्र पर थोड़ी अधिक ब्याज दर मिलनी चाहिए। इन विवेचनों में सन्तुलन लाते हुए, मैं लघु बचत प्रपत्रों पर ब्याज की मौजूदा दरों में किसी भी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं करता हूं। इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष पीपीएफ, जीपीएफ और विशेष जमा योजना पर 8 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। वयोवृद्ध नागरिकों के लिए मैं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें 9 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर दी जाएगी। अन्य सभी नागरिकों के लिए मैं भारतीय रिजर्व बैंक बांड जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं जिसपर 8 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर दी जाएगी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना अब आवश्यक प्रतीत नहीं होती है क्योंकि नई बचत योजना में वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त रूप से कवर किया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

75. दसवीं योजना के दस्तावेज में योजना आयोग ने यह सुझाव दिया था कि खाद्य स्टाम्प वितरित करने की प्रणाली का परीक्षण प्रायोगिक आधार पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक पात्र परिवार एक निर्दिष्ट वितरण केन्द्र से खाद्य स्टाम्पों का मासिक कोटा प्राप्त करने का हकदार होगा और फिर इन स्टाम्पों का प्रयोग किसी खाद्य दुकान से खाद्यान्न खरीदने में किया जा सकता है। मैं एक चयनित राज्य में दो या तीन परस्पर सटे जिलों में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्य वितरित करने के स्थान पर खाद्य स्टाम्प वितरित करने की प्रायोगिक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि कोई एक राज्य इस प्रयोग में केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करने में आगे आएगा।

लिंग बजटीय व्यवस्था

76. महिलाओं के एक दल ने मुझसे भेंट की तथा मुझसे आग्रह किया कि मैं लिंग बजटीय व्यवस्था पर विचार करूं। इसका अभिप्राय यह है कि बजट आंकड़े इस प्रकार से पेश किए जाएं कि बजट आवंटनों में लिंग संवेदनशीलताओं को स्पष्ट तौर पर उजागर किया जाए। 'सरकारी लेनदेनों की वर्गीकरण प्रणाली' सम्बन्धी एक विशेषज्ञ समूह ने 6 जुलाई, 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसने आंकड़ा संग्रहण की उचित प्रणालियाँ तथा बजट में उनको प्रतिनिधित्व दिए

जाने के बारे में अपनी सिफारिश प्रदान की हैं। इस समूह ने समय-समय पर लाभ-स्थिति विश्लेषण को प्रारम्भ करने की भी सिफारिश की है। सरकार इन सिफारिशों की जांच करेगी तथा मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन वर्ष 2005-06 के बजट में करना मेरे लिए सम्भव होगा।

सब्सिडी

77. सात वर्ष पहले, मैंने संसद के समक्ष सब्सिडियों पर पहला दस्तावेज रखा था। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इस बात का संकल्प लिया गया है कि सभी सब्सिडियां पूर्णतः गरीबों तथा लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूर तथा शहरी गरीबों जैसे वास्तविक जरूरतमंद लोगों के लिए लक्षित होंगी। मैंने राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान से कहा है कि वह इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक खाका तैयार करे। मुझे विश्वास है कि संसद के अगले सत्र में सदन के समक्ष मैं इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करूंगा।

राज्यों की वित्तीय व्यवस्था

78. राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जुटाए गए करों का भारी अनुपात राज्यों को अन्तरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार राज्यों को ऋण भी प्रदान करती है। चालू वर्ष के बजट अनुमानों के प्रकाश में, मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यों की भागीदारी ब.अ. 2003-04 में 63,758 करोड़ रुपए से बढ़कर 82,227 करोड़ रुपए हो जाएगी। हम दूसरे तरीकों से भी राज्यों की सहायता कर रहे हैं। उन तरीकों में एक है- ऋण अदला-बदली योजना। मैं ऋण अदला-बदली की सुविधा देने का प्रस्ताव करता हूं जिसके अंतर्गत राज्यों को नए ऋण लेने तथा अपने उच्च लागत वाले ऋणों की वापसी अदायगी नाबार्ड तथा अन्य एजेंसियों को करने की अनुमति होगी। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि उन्हें मुक्त बाजार ऋणों में वृद्धि करने तथा केन्द्र सरकार के ऋणों पर उनकी निर्भरता घटाने की अनुमति देने के संबंध में राज्यों से परामर्श किया जाए। मैं परस्पर मुद्रा आधार पर राज्यों को विदेशी ऋण प्रदान किए जाने पर भी विचार करूंगा।

79. हम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर संसाधनों के अंतरण के माध्यम से राज्यों को अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य राजकोषीय विवेक तथा वित्तीय अनुशासन के पालन संबंधी दायित्व को स्वीकार करेंगे।

80. केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों पर 12.5 प्रतिशत ब्याज दर लगती थी। 2003-04 में इस दर को कम करके 10.5 प्रतिशत कर दिया गया। इस दर में और कटौती करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। 1 अप्रैल, 2004 से राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। इससे, केवल इसी वर्ष के दौरान राज्यों को 375 करोड़ रुपए का लाभ होगा।

विशेष आर्थिक पैकेज

81. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत यह वायदा किया जाता है कि विगत में बिहार, जम्मू और काश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए घोषित विशेष आर्थिक पैकेजों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, बिहार में बहुत सी परियोजनाएं, जिनमें विद्युत, सड़कों, जलनिकासी तथा विस्थापित लोगों के पुनर्वास संबंधी परियोजनाएं भी शामिल हैं, काफी समय से लम्बित पड़ी हैं। मैं सदन को आश्चस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सम विकास योजना के माध्यम से बिहार की सहायता की जाएगी। इसके लिए अभी 3225 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है तथा यदि आवश्यक हुआ तो इस राशि में वृद्धि की जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.)

82. सरकार पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के शीघ्र विकास के लिये वचनबद्ध है। तदनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए अपने योजना बजट का कम से कम 10 प्रतिशत आबंटित करने का आदेश दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय करने के लिये यह आबंटन 5823 करोड़ रुपए का होगा। इस 10 प्रतिशत के आबंटन से खर्च न की गई शेष धनराशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के व्ययगत न होने वाले केन्द्रीय संसाधन पूल में अंतरित की जाएगी। चालू वर्ष में इस क्षेत्र की विशिष्ट परियोजनाओं एवं स्कीमों के लिये केन्द्रीय संसाधन पूल से 650 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं जो 2003-04 के 550 करोड़ रुपए से अधिक हैं।

जम्मू एवं कश्मीर

83. सरकार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को उचित योजना आकार के लिये विशेष सहायता प्रदान करेगी। काफी समय से लंबित बागलीहार परियोजना के लिये भी यह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार भी बैंक आफ जम्मू एण्ड कश्मीर के साथ वर्तमान ओवरड्राफ्ट करार से भारतीय रिजर्व बैंक की अर्थोपाय स्कीम में सुचारु रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु राज्य को 300 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने के लिये सहमत हो गई है।

पिछड़ा राज्य आयोग

84. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में पिछड़े राज्य अनुदान आयोग का सृजन करना निहित है जिसका उपयोग ऐसे राज्यों में उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिये किया जाएगा। इसमें यह भी निहित है कि केन्द्र सरकार से सभी असांविधिक संसाधन अन्तरण गरीब एवं पिछड़े राज्यों के पक्ष में दिये जायेंगे परन्तु निष्पादन पैरामीटर भी ध्यान में रखे जायेंगे।

85. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार 25,000 करोड़ रुपए की आरंभिक निधि (कार्पस) के साथ एक पिछड़े राज्य अनुदान निधि की स्थापना करेगी और यह धनराशि 5 वर्ष की अवधि में प्रदान की जाएगी। लगभग 1800 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय वाली मौजूदा पिछड़े जिले पहल योजना का जहां इस अनुदान निधि में विलय किया जाएगा, वहीं 5,000 करोड़ रुपए के वार्षिक अंशदान के लिए अपेक्षित शेष राशि को योजना के लिए कुल केन्द्रीय सहायता में से चिह्नित किया जाएगा। आशा है कि इससे एक निश्चित समयावधि में देश के निर्धनतम और सबसे पिछड़े जिलों में सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचा कार्यक्रमों को आरम्भ किया जा सकेगा। यह निधि वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रचालन में आएगी। आगे के ब्यौरे योजना आयोग के साथ परामर्श से तय किए जाएंगे।

रक्षा आधुनिकीकरण

86. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए वायदे के अनुसार, सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण में होने वाले सभी विलम्बों को समाप्त करने के लिए, कटिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा संबंधी पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति का सम्मान करते हुए, इस वर्ष उच्च आवंटन करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, मैं रक्षा के लिए आवंटन को बढ़ाकर 77,000 करोड़ रुपए (बजट अनुमान 2003-04 के 65,300 करोड़ रुपए की तुलना में) करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए 33,483 करोड़ रुपए (बजट अनुमान 2003-04 के 20,953 करोड़ रुपए की तुलना में) का आवंटन भी शामिल है।

2004-2005 के बजट अनुमान

87. अब, मैं चालू वर्ष के लिए बजट अनुमानों की ओर रुख करता हूं।

आयोजना व्यय

88. बजट तैयार करते समय मैंने पाया कि आयोजना गत स्कीमों की बहुलता है। इन स्कीमों की संख्या, किस्म और यहां तक कि वे संक्षिप्ताक्षर जिनसे इन्हें जाना जाता है, विभ्रमकारी हैं। मैंने यह भी पाया कि कई ऐसी स्कीमों हैं जिनके उद्देश्य लगभग एक से हैं। कुछ मामलों में सभी स्कीमों एक ही मंत्रालय या विभाग में अवस्थित थीं, अन्य मामलों में वे अलग-अलग मंत्रालयों या विभागों के बीच बंटी हुई थीं। आयोजना स्कीमों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है - केन्द्रीय क्षेत्रक, राज्य क्षेत्रक और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह अपेक्षित है कि राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे परिवार योजना के अतिरिक्त सभी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों राज्यों को अंतरित की जाएंगी। सौभाग्यवश एक नया योजना आयोग हमारे सामने है और मुझे विश्वास है कि योजना आयोग योजनाओं के इस उलझाव को व्यवस्थित करेगा।

89. वर्ष 2004-05 के लिए आयोजना व्यय वर्ष 2003-04 की अनन्तिम वास्तविक राशि 122,149 करोड़ रुपए की तुलना में 145,590 करोड़ रुपए आंका गया है, जहां एक और आयोजना राजस्व व्यय में वर्ष 2003-04 में 78,537 करोड़ रुपए से वृद्धि होकर यह 91,843 करोड़ रुपए हो गया, वहीं आयोजना पूंजी व्यय वर्ष 2003-04 में 43,612 करोड़ रुपए से बढ़कर 53,747 करोड़ रुपए हो गया जो तीव्र और स्वागत योग्य बढ़ोतरी है।

आयोजना-भिन्न व्यय

90. वर्ष 2004-05 में आयोजना-भिन्न व्यय के 332,239 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो वर्ष 2003-04 की अनन्तिम वास्तविक राशि 349,787 करोड़ रुपए से अपेक्षाकृत कम है जिसमें राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को पुनर्दायगी किया जाने वाला 46,211 करोड़ रुपए का पूंजी व्यय शामिल है। अन्तरिम बजट के आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि मुख्यतः रक्षा में पूंजी व्यय (11,000 करोड़ रुपए) तथा भारतीय टेलिफोन उद्योग लि. को सहायता प्रदान करने की वजह से है।

राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा

91. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 477,829 करोड़ रुपए आंका गया है जिसमें से आयोजना के तहत 145,590 करोड़ रुपए तथा आयोजना-भिन्न के लिए 332,239 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। मेरा अनुमान है कि केन्द्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 309,322 करोड़ रुपए तथा राजस्व व्यय 385,493 करोड़ रुपए होगा। परिणामस्वरूप, राजस्व घाटा 76,171 करोड़ रुपए आंका गया है जो सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के समकक्ष है तथा जो वर्ष 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत (अनन्तिम वास्तविक राशि के अनुसार) के तदनुसारी अनुमानों से एक प्रतिशत अंक नीचे है। राजकोषीय घाटा 137,407 करोड़ रुपए आंका गया है जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है।

भाग ख

XI. कर प्रस्ताव

92. मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा।

93. कराधान राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह वायदा किया गया है कि 'कर दरें टिकाऊ और अभिवृद्धि अनुपालन व निवेश के लिए प्रेरक' होंगी। 1990 के दशक में शुरू की गई नीतियों को आधार के साथ प्रत्यक्ष कर दरें अब संयत हैं और उन्हें समय-समय पर सिर्फ दुरुस्त करते रहने की आवश्यकता है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में सुविचारित कमी के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर भी संतुलित हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष कर राजस्व का अनुपात 1990-91 में 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 3.8 प्रतिशत हो गया। प्रत्याशा के अनुरूप सकल घरेलू उत्पाद में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का अनुपात 1990-91 में 7.9 प्रतिशत से गिरकर 2003-04 में 5.3 प्रतिशत के अनुपात के साथ और तेजी से गिर गया। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इसका कमजोर बिंदु है। उत्पाद शुल्क राजस्व सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत के आसपास कुछ हठधर्मिता के साथ अटके हुए हैं। उत्पाद शुल्क दरों में कटौती अंशतः इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है, विनिर्माण उद्योग के विस्तार से हमें कुछ अधिक राजस्व मिलना चाहिए था।

94. मेरी कराधान संबंधी नीतियों के माध्यम से मैं यह संकेत देना चाहता हूँ कि हम कर दरों में संयम व स्थायित्व के प्रति वचनबद्ध रहें; कि हम प्रत्यक्ष करों व उत्पाद शुल्कों से राजस्व बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध रहें; कि हम सेवा कर तंत्र के विस्तार के प्रति वचनबद्ध रहें क्योंकि सेवा कर सकल घरेलू उत्पाद का 51 प्रतिशत बैठता है। मैं कर नीतियों का प्रयोग विशेष प्रकार के निवेश को प्रोत्साहन देने और बाजार में विशेष प्रकार के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए भी करूंगा।

95. मैं कर सुधारों का समर्थक हूँ परन्तु मेरी तरफ से यह बुद्धिमतापूर्ण नहीं होगा कि कर सुधारों का प्रयास अति शीघ्रता से या थोड़ा-थोड़ा करके करूं। अब से सात माह पश्चात् दूसरा बजट होगा और तब कर सुधार के विषय में चर्चा करने का मौका मिलेगा।

प्रत्यक्ष कर

96. मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको अच्छे समाचार देना चाहूंगा। एक लाख रुपये (100,000 रुपये) तक की कर योग्य आय वाले किसी भी व्यक्ति को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। इस निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं था। जहां कर दरें कम हैं वहां कर स्लैब विचारणीय समस्या होती है। परन्तु मैं कर-स्लैब बदलने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं ऐसे समय में राजस्व की बड़ी धनराशि से वंचित नहीं हो सकता जब सरकार ने निवेश और कल्याण कार्यक्रमों के लिये एक बड़ा उत्तरदायित्व लिया है। आयकर विवरणियां दाखिल करने वाले लगभग 3.4 करोड़ व्यक्तियों में से केवल 2.7 करोड़ व्यक्ति कर दाता होते हैं। मेरे प्रस्ताव से 1.4 करोड़ कर निर्धारितियों को राहत मिलेगी। मैंने जो पद्धति अपनाई है वह कुछ नई है। जहां प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान कर-स्लैब और कर दरों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगा और अपनी कर योग्य आय एवं देय कर की संगणना करेगा वहां 100,000 रुपये की कर योग्य आय वाले व्यक्ति को आयकर देयता से स्वतः छूट प्राप्त हो जाएगी। मैं इस बजट में अधिक राहत, अथवा सभी के लिये राहत नहीं दे सकता। यदि इसके अनुपालन में सुधार हुआ तो मैं इस विषय पर पुनः सोचने का वचन देता हूँ।

97. मैं पात्र करदाताओं के कुछ वर्गों को राहत देने का प्रस्ताव रखता हूँ। तदनुसार मैं सैन्य ~~संभालन~~ कार्यों के दौरान मारे गए सशस्त्र बलों तथा अर्धसैनिक बलों के सदस्यों की विधवाओं, बच्चों तथा नामित उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली परिवार पेंशन को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखता हूँ। उनके सर्वोत्कृष्ट बलिदान के प्रति यह मेरा विनम्र अभिवादन है।

98. मैं स्वलीन (ओटिज्म), प्रमस्तिष्कीय अंगघात तथा बहुमुखी अपंगता से पीड़ित व्यक्तियों को धारा 80घघ तथा धारा 80प का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

99. किसानों द्वारा यह बात मेरे ध्यान में लाई गई है कि कुछ शहरी समूहों में स्थित कृषि भूमि पूंजीगत परिसम्पत्ति की परिभाषा में शामिल किया जाता है तथा ऐसी भूमि के अधिग्रहण से मिलने वाले मुआवजे पर पूंजीलाभ कर लगाया जाता है। ऐसे मुआवजे को पूंजी लाभ कर से मुक्त रखा जाना चाहिए। मैं ऐसे सभी मामलों में, जिनके अंतर्गत 1 अप्रैल, 2004 अथवा उसके पश्चात् मुआवजा अथवा संबंधित मुआवजा प्राप्त किया गया है, यह छूट प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

100. केन्द्र सरकार की सेवा में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों के लिए इस वर्ष पहली जनवरी, 2004 से एक नई 'परिभाषित अंशदान' पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अंशदानों के कर प्रबंधन ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस संबंध में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत ईईटी फार्मूले को अपनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। इस फार्मूले के अंतर्गत कर प्रयोजनों हेतु अंशदानों को आय से अलग रखा जाएगा; उपचित राशि को भी कर से मुक्त रखा जाएगा; तथा केवल अंतिम रूप से मिलने वाले लाभ पर उसकी प्राप्ति के वर्ष में लागू दर पर कर लगाया जाएगा।

101. मैं कुछ ऐसी छूटों को वापिस लेने का प्रस्ताव रखता हूँ जिनकी उपयोगिता अब समाप्त हो गई है। अनिवासी (बाह्य) से अर्जित ब्याज तथा विदेशी मुद्रा में जमाराशियों पर बैंकों द्वारा अनिवासी अथवा असाधारण निवासी को अदा किया गया ब्याज अब कर से मुक्त नहीं होगा। इसी प्रकार, किसी विदेशी राज्य अथवा विदेशी उद्यम से हवाई जहाज अथवा उसका इंजन लीज पर प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा की गई अदायगी कर से मुक्त नहीं होगी। यह छूट 1 सितम्बर, 2004 के पश्चात् समाप्त हो जाएगी।

102. माननीय सदस्य जानते हैं कि मैंने 1997 में उपहार कर समाप्त कर दिया था। वह निर्णय अभी भी कायम है लेकिन काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने से (मनी लांडरिंग) रोकने के लिए बचाव के कुछ रास्तों को बंद करने की आवश्यकता है। तदनुसार गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त होने वाले 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाले ऐसे सभी उपहारों को आय मान कर उन पर कर लगाया जाएगा। रक्त संबंधियों, पूर्वजों एवं वंशजों से प्राप्त उपहारों तथा विवाह जैसे कतिपय अवसरों पर प्राप्त होने वाले उपहारों को कर से पूर्णतः मुक्त रखा जाएगा।

103. एग्रो-प्रसंस्करण उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं अधिनियम की धारा 80झख में संशोधन का प्रस्ताव करता हूँ ताकि फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, रख-रखाव तथा पैकेजिंग हेतु स्थापित नए एग्रो-प्रसंस्करण उद्योगों को 5 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत लाभ की छूट तथा आगामी 5 वर्षों हेतु 25 प्रतिशत लाभ की छूट की अनुमति दी जा सके।

104. सरकार को विनिर्माण क्षेत्र में निवेश पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए, मैं किसी मौजूदा उपक्रम द्वारा अधिग्रहित अथवा संस्थापित नए संयंत्र तथा मशीनरी पर धारा 32(1)(ii) के अन्तर्गत 15 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यहास को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, संस्थापित क्षमता में अब अपेक्षित वृद्धि 25 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत होगी।

105. ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने अच्छा कार्य किया है और इसे प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं ऑटोमोबाइल उद्योग को एक ऐसे उद्योग के रूप में करने का प्रस्ताव करता हूँ जो विभागीय अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं पर होने वाले व्यय का 150 प्रतिशत छूट प्राप्त करने का हकदार होगा।

106. विद्युत क्षेत्र को भी कर रियायतों की जरूरत है। विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत निर्माण, पारेषण तथा वितरण की अलग-अलग व्यवस्था की गयी है। मौजूदा पारेषण तथा वितरण लाइनों के पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु मैं ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में धारा 80झक के तहत लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ जिन्हें 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2006 के दौरान हाथ में लिया गया है।

107. नौवहन उद्योग ने टनभार कर लगाने की मांग की है ताकि इसको इरादतन प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सके। टनभार कर से और अधिक पोतों को भारतीय पत्तनों पर आवाजाही को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इस अनुरोध पर अपनी सहमति का प्रस्ताव करता हूँ। इसके परिणामस्वरूप, धारा 33कग के अन्तर्गत प्रदत्त रियायती व्यवस्था को वापस ले लिया जाएगा तथा पोत-परिवहन कम्पनियों के पास टनभार कर अथवा लाभ पर सामान्य कारपोरेट कर के भुगतान का एकमात्र विकल्प मौजूद रहेगा।

108. मैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए 100 अथवा अधिक बिस्तरों वाले नए अस्पतालों को धारा 80झख का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूँ। ऐसे अस्पतालों को पांच वर्ष की अवधि के लिए उनके लाभ पर 100 प्रतिशत कटौती की छूट प्राप्त होगी।

109. आवास उद्योग को 31 मार्च, 2005 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धारा 80झख के अंतर्गत कतिपय लाभ प्राप्त हैं, इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2007 करने का प्रस्ताव करता हूँ।

110. मुम्बई शहर में अनुमोदित योजनाओं के अंतर्गत मौजूदा भवनों के पुनर्निर्माण और विकास में एक छोटी समस्या पैदा हुई है, सम्भवतः यह समस्या अन्य शहरों में भी है। अतः मैं आवासीय परियोजनाओं के मामले में एक एकड़ के न्यूनतम भूखण्ड आकार की शर्त में छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ बशर्ते कि ये परियोजनाएं केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्निर्माण और विकास की योजना के अनुसार कार्यान्वित की जाएं।

111. पूंजी अनुलाभ कर दूसरा पेचीदा मुद्दा है। पूंजी बाजार लेन देनों पर लागू करने से यह और भी जटिल हो जाता है। दीर्घकालिक और अल्पकालिक की परिभाषाओं और दो प्रकार के अनुलाभों को दिये गये विभेदक कर व्यवहारों के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। इसके आसान उत्तर नहीं हैं, परन्तु मैंने प्रतिभूतियों के लेन-देन पर करों की पुनर्संरचना द्वारा एक शुरुआत करने का निर्णय लिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघीय सूची में प्रविष्टि 90 को विवेकपूर्ण तरीके से शामिल किया था। उस प्रविष्टि का अनुसरण करते हुए मैं प्रतिभूति लेन देनों से दीर्घकालिक पूंजी अनुलाभों पर कर समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके स्थान पर मैं शेयर बाजारों में प्रतिभूतियों के लेन देन पर एक छोटा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह दर प्रतिभूति के मूल्य का 0.15 प्रतिशत होगी। इस प्रकार एक लाख रुपये के मूल्य वाली प्रतिभूति के लेनदेन पर अब 150 रुपये का छोटा सा कर लगाया जाएगा। यह कर खरीददार पर लगाया जाएगा। प्रतिभूतियों से अल्पकालिक अनुलाभों के मामले में, मैं कर की दर

घटाकर समान 10 प्रतिशत की दर का प्रस्ताव करता हूँ। मेरी गणना यह प्रदर्शित करती है कि नई कर प्रणाली सभी संबंधितों के लिये प्रसन्नता का विषय होगी।

112. मैं पारस्परिक निधियों द्वारा वितरित लाभांशों पर कर में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इक्विटी-उन्मुख पारस्परिक निधियों पर कर से छूट जारी रहेगी। ऋण संबंधी पारस्परिक निधियों को अब यूनिट धारकों में वितरित आय का 12.5 प्रतिशत भाग को रोक कर (विदहोल्ड) रखना होगा। व्यक्तियों तथा हिन्दु अविभाजित परिवारों को इस दर पर लाभ मिलना जारी रहेगा। तथापि, निगमित यूनिट धारकों के मामले में, मैं 20 प्रतिशत की दर का प्रस्ताव रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि कार्पोरेट इस बात को समझेंगे क्योंकि मैं केवल मध्यस्थता अवसर संबंधी खिड़की को आंशिक रूप से थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ।

113. अधिनियम की धारा 94 में उपयुक्त संशोधन करके बोनस-स्ट्रिपिंग तथा लाभांश-स्ट्रिपिंग को समाप्त करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

114. मैं कराधार का विस्तार करने तथा राजस्व संबंधी रिसाव (लीकेज) को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय करने का भी प्रस्ताव रखता हूँ। ऐसे प्रत्येक उपाय का विवरण देकर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता।

115. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) का दायरा कुछ और कार्यकलापों तक बढ़ाया जा रहा है। धारा 40 (क) (i) तथा धारा 194ग में संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।

116. दूरसंचार क्षेत्रक को 31 मार्च, 2004 से पूर्व शुरू की गई सेवाओं के लिए धारा 80झक के अंतर्गत कतिपय लाभ प्राप्त थे। दूरसंचार क्षेत्रक की आवश्यकताओं की विस्तृत जांच के लम्बित रहते, मैं इसकी समाप्ति की तारीख 31 मार्च, 2005 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

117. वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के कार्य में लगी तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व अनुमोदित कंपनियां 10 वर्ष के लिए शत प्रतिशत छूट की हकदार हैं। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के अनुरोध पर और एक विस्तृत जांच के लम्बित रहते, मैं इसकी समाप्ति की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2005 करने का प्रस्ताव करता हूँ।

118. जम्मू व कश्मीर में 31 मार्च, 2004 से पूर्व उत्पादन आरम्भ करने वाले औद्योगिक उपक्रमों को शत प्रतिशत कर छूट प्राप्त थी। जम्मू व कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित प्रोत्साहनों की विस्तृत जांच के लम्बित रहते, मैं यह तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2005 करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अप्रत्यक्ष कर

119. मैं अब अपने अप्रत्यक्ष करों की ओर आता हूँ। नीतिगत संकेत जिसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता है वह है कि सीमा शुल्कों को नये तुले तरीके से कम किया जाएगा। मेरा इरादा है कि भारत के शुल्क ढांचे को एशियान देशों की पंक्ति में लाऊँ। आखिरकार, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की एक समान दर होनी चाहिए। पिछले चार वर्षों के दौरान मेरे पूर्ववर्तियों ने उत्पाद शुल्कों को समंजित किया और उन्हें केंद्रीय मूल्य वर्द्धित कर दर (सेनवेट) की ओर ले गए। वह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक महत्ववाली वस्तुओं को 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क वहन करना होगा।

120. दूसरा सिद्धांत जिस पर बल दिए जाने की आवश्यकता है वह है कि जहां उत्पाद शुल्क लगाया जाए, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे माल जब आयात किया जाए तो उस पर समतुल्य प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी) लागू होना चाहिए। मेरे कर प्रस्तावों में मैंने इसलिए कुछ आयातित माल द्वारा लिए जा रहे प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से छूट को हटा दिया है जहां भारत में बने माल पर उत्पाद शुल्क से कोई तदनुरूपी छूट नहीं है।

121. मैं यह भी इंगित करूंगा कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आपस में जुड़े हुए हैं। किसी क्षेत्रक के लिए कर व्यवस्था पर विचार करते समय हमें उस क्षेत्रक पर लागू सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क को ध्यान में रखना चाहिए।

122. जनवरी, 2004 में सीमा-शुल्क की अधिकतम दर घटाकर 20 प्रतिशत की गई थी। मैं शेष चालू राजकोषीय वर्ष के लिए इस अधिकतम दर को बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूं।

123. मैं अब धातुओं, खनिजों और औद्योगिक कच्चे माल से शुरू करते हुए विशिष्ट क्षेत्रकों के बारे में चर्चा करूंगा। इस्पात एक अग्रणी धातु है। सामान्यतः इस पर 16 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क होना चाहिए। तथापि, इस वर्ष फरवरी, मैं, इस्पात पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया था परन्तु इस चेतावनी के साथ कि नियमित बजट प्रस्तुत करने के समय इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी। आशाओं के विपरीत इस्पात के मूल्यों में कमी नहीं आई है बल्कि ये तेजी से बढ़े हैं। मैं अमिश्र इस्पात पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत करने और इस्पात पर उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क आयातों पर भी लागू होगा। मुझे आशा है कि फरवरी 2004 के बाद से हुई कुछ राजस्व क्षतियों की पूर्ति हो सकेगी।

124. मिश्र इस्पात, तांबा, शीशा, जस्ता और मूल धातुएं विभिन्न उद्योगों में काम आने वाले कुछ बुनियादी कच्चे माल हैं। मैं इन धातुओं पर अधिकतम दर घटा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं गलनरोधी कच्चे खनिजों और ग्रेफाइट, एस्बेस्टोस, अभ्रक और जिप्सम जैसे खनिज उत्पादों पर भी सीमा शुल्क घटा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। सभी उद्देश्यों पर भी सीमा शुल्क 15 प्रतिशत होगा।

125. मैं कृषि क्षेत्रक को कतिपय रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूं। मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए कच्चे पॉम आयल पर सीमा शुल्क 65 प्रतिशत बनाए रखते हुए मैं टैरिफ आयोग की सिफारिश स्वीकार करते हुए रिफाइंड पाम आयल पर शुल्क बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

126. बागान मशीनरी की कुछ मदों पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया जाता है। मैं चाय और काफी बागान क्षेत्रक से सम्बन्धित और अधिक मदों पर रियायती दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

127. उत्पाद शुल्क के क्षेत्र में मैं अनेक रियायतों का प्रस्ताव करता हूं। ट्रेक्टरों पर 16 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगता है। अब ट्रेक्टर पूरी तरह शुल्क मुक्त होंगे। इसी तरह डेयरी मशीनरी जिस पर 16 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगता है, को पूरी छूट प्राप्त होगी। हाथ के औजार जैसे फावड़े, बेलचे और दरातियों, जिन पर इस समय 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क वसूला जाता है, भी पूरी तरह उत्पाद शुल्क मुक्त होंगे।

128. मांस, मुर्गी और मत्स्य व्यंजनों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत किया जाएगा और फूड ग्रेड हेक्सेन (खाद्य तेल उद्योग में प्रयुक्त) पर उत्पाद शुल्क 32 प्रतिशत से घटा कर 16 प्रतिशत किया जाएगा।

129. मैं स्वास्थ्य क्षेत्रक को कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूँ। विकलांगों के लिये अनेक मदों पर पहले ही आयात शुल्कों से छूट प्राप्त है या उन पर 5 प्रतिशत का रियायती शुल्क लगाया जाता है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि टाकिंग बुक्स, ब्रेल कम्प्यूटर टर्मिनल, ब्रेल-राइटर्स और टाइपराइटर्स, सहायक श्रवण यंत्रों, कोचलियर इम्प्लांट्स और स्टेयर लिफ्टों जैसी पुनर्वास सहायता सामग्रियों को सीमाशुल्क से पूरी छूट दी जाय। उन्हें उत्पाद शुल्क और सीबीडी से भी छूट दी जाएगी। विकलांगों के लिये वैशाखियों, व्हील चेयर्स, वाकिंग फ्रेम्स, कृत्रिम अंगों आदि को भी सीमा शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी। आयात शुल्क छूट प्राप्त कर रही दृष्टिहीनों एवं बधिरों से संबंधित संस्थाओं पर कुछ प्रतिबंध हैं। मैं इन प्रतिबंधों को हटाने और छूट प्राप्त उपकरणों की सूची बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार और नगरपालिका अस्पतालों द्वारा उपयोग किये जा रहे एंबुलेंसों पर ही 16 प्रतिशत के रियायती उत्पाद शुल्क की स्वीकृति दी गई है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रकार पंजीकृत सभी एंबुलेंस इस लाभ के हकदार होंगे। केवल हेपेटाइटिस बी का पता लगाने वाले नैदानिक किटों पर ही उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। मैं सभी प्रकार के हेपेटाइटिस का पता लगाने वाले किटों पर यह छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

130. सेनवेट दर की दिशा में बढ़ने के लिये मैं कांटेक्ट लेंसों और ताशों पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं वैक्यूम फ्लारस्क प्लास्टिक इंसुलेटेड वेयर, सुगंधित सुपारी, प्रीफैब्रीकेटेड बिल्डिंग्स, प्रयोगशाला ग्लासवेयर, श्याम-श्वेत टेलीविजन सेटों, पापुलेटेड पी.सी.बी, नकली आभूषणों, मोमबत्तियों और दीवार-घड़ियों एवं हाथ की घड़ियों सहित कुछ मदों पर उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सभी मामलों में सामान्य लघु उद्योग छूट जारी रहेगी और इससे उपभोक्ताओं और छोटे विनिर्माताओं पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अन्य विनिर्माता भी सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करेंगे।

131. गैर-यंत्रीकृत क्षेत्रक में उत्पादित दियासलाइयों के संरक्षण के लिये, मैं यंत्रीकृत/अर्ध यंत्रीकृत क्षेत्रक में उत्पादित दियासलाइयों पर उत्पाद शुल्क सेनवेट क्रेडिट के बिना 8 प्रतिशत से बढ़ाकर सेनवेट क्रेडिट सहित 16 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

132. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को कमोवेश कर समाहर्ता की पहुंच से बाहर रखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत सीमा शुल्क को वर्ष 2005 में शून्य स्तर तक नीचे लाया जाएगा। फिलहाल, मैं समझौते के तहत आबद्ध दरों का पालन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

133. मैं कैथोड रे ट्यूबों के हिस्सों के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों तथा मोबाइल हैंड सेटों के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं, प्लाज्मा डिसप्ले पैनल आदि के लिए उत्पाद शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूँ। मैं टेलीकॉम श्रेणी के ऑप्टिकल फाइबर तथा केबिल के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट मदों को भी सीमाशुल्क से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। सेलुलर मोबाइल टेलिफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा आयातित मोबाइल स्वीचिंग केन्द्रों को अब सीमा शुल्क से छूट प्राप्त होगी। मैं सार्वभौम पहुंच सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए आयातों के सम्बन्ध में छूट का प्रस्ताव करता हूँ।

134. कम्प्यूटर पर 8 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है। मैं इसे पूर्ण छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

135. मैं 2000 रुपए तक की एमआरपी वाली एलपीजी गैस स्टोवों, 250 रुपए तक की एमआरपी वाले फुटवीयर तथा 200 रुपए तक की एमआरपी वाली लेखन सामग्रियों पर कुछ सीमा तक शुल्क राहत प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

136. मैं मनोरंजन सवारियों पर उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।
137. वाणिज्य मंत्री रहने के कारण निर्यात प्रोत्साहन में मेरी गहरी रुचि है। मैं पूंजीगत वस्तुओं पर 5 प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसका उपयोग चर्म उद्योग से लेकर गैर-चर्म फुटवीयर उद्योगों द्वारा किया जा रहा है।
138. सभी प्रकार के तैयार शुदा चमड़े को सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है। मैं पेटेंट चमड़े पर भी इस छूट का प्रस्ताव करता हूँ।
139. आभूषण उद्योग में स्वर्ण के सम्बन्ध में प्लैटिनम एक गम्भीर चुनौती है। दोनों को एक समान माना जाए। इसलिए मैं प्लैटिनम पर प्रति 10 ग्राम पर लगने वाले 550 रुपये के आयात शुल्क को घटाकर 200 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं खुरदरे अर्द्धबहुमूल्य पत्थरों की भांति रंगीन बहुमूल्य रत्नों को भी सीमा शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूँ।
140. उत्पाद शुल्क से क्षेत्र-विशिष्ट छूटें समय-समय पर दी गई हैं। पूर्वोत्तर राज्य व जम्मू और कश्मीर अपने आप में एक श्रेणी हैं। उनके द्वारा प्राप्त छूट जारी रहेंगी। सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश को भी क्षेत्र-आधारित छूट दी गई थी। माननीय सदस्य इसके पक्ष में तर्कों और विरोध में तर्कों से पूरी तरह अवगत हैं। मुझे दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष रहना है। तदनुसार, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पूर्वोत्तर राज्यों व जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त राज्यों को प्राप्त क्षेत्र विशिष्ट छूटें जारी रहेंगी और ये 31 मार्च, 2007 से पहले स्थापित या विस्तारित इकाइयों को उपलब्ध होंगी।
141. मैं अब सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कर समस्या की चर्चा करता हूँ जिसका मैंने इस वर्ष सामना किया है। यह कपड़ा क्षेत्रक से संबंधित है। पिछले वर्ष हथकरघा व विद्युत करघा को सेनवेट श्रेणी में लाया गया था। इसका आशय अच्छा था परन्तु मुझे डर है कि इस निर्णय में देश में वस्त्रों के उत्पादन की विकेंद्रित व बंटी हुई प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त, तथाकथित सेनवेट श्रेणी में विभिन्न चरणों में लगभग 40 छूटें हैं। वास्तव में, निर्णय के पश्चात दो छूटें जोड़ी गई हैं।
142. मुझे विदित है कि कपड़ा व वस्त्र संबंधी करार 31 दिसंबर, 2004 को समाप्त हो जाएगा। हमारे कपड़ा उद्योग को अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। जो अपनी संगठनात्मक शक्ति के कारण प्रतियोगिता कर सकें, उन्हें प्रतियोगिता करने की अनुमति होनी चाहिए; शेष के लिए, हमें अनिवार्य कर व्यवस्था का अनुपालन करने के लिए अधिक समय देना होगा। इसके साथ ही बराबरी की व्यवस्था होनी चाहिए।
143. यदि मैंने माननीय सांसदों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की भावना को सही समझा है, तो मुझे विश्वास है कि हथकरघा और बिजलीकरघा क्षेत्रकों को सेनवेट व्यवस्था से मुक्त करने की सार्वभौम मांग रही है। इन जटिल मसलों पर पूरी तरह विचार करने के बाद मैं अनिवार्य सेनवेट शुल्क को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके स्थान पर मैं कपड़ा उद्योग क्षेत्रक के लिए एक नई कर व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस कवायद में मुझे कपड़ा मंत्री का पूरा समर्थन प्राप्त है।
144. मैं अब संक्षेप में नई व्यवस्था को स्पष्ट कर दूँ:
- सर्वप्रथम, अनिवार्य सेनवेट श्रृंखला को समाप्त किया जाएगा।

- दूसरा, शुद्ध सूत, ऊन और रेशम पर चाहे वह रेशा, धागा, कपड़ा हो या परिधान, कोई अनिवार्य उत्पाद शुल्क नहीं होगा।
- तीसरा, मिश्रित कपड़ों और शुद्ध गैर सूती कपड़ों (पोलिस्टर, विस्कोस, एक्रिलिक और नायलॉन) के लिए अलग कर व्यवस्था होगी।
- चौथा, मानव-निर्मित स्टेपल रेशे पर 16 प्रतिशत; पोलिस्टर फिलामेंट धागे (टेक्सचर्ड धागे सहित) पर 24 प्रतिशत; और अन्य मानव-निर्मित फिलोमेंट धागे (टेक्सचर्ड धागे सहित) पर 16 प्रतिशत अनिवार्य उत्पाद शुल्क होगा।

145. प्रत्येक विनिर्माता चाहे वह हथकरघा या बिजलीकरघा या सम्मिश्रित कारखाना-के पास दो मार्गों में से एक को चुनने का विकल्प होगा। इनमें से एक छूट का मार्ग होगा और दूसरा सेनवेट मार्ग होगा। छूट मार्ग के अंतर्गत किसी भी अवस्था में (सिवाय मानव-निर्मित रेशे और फिलामेंट धागे के) कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं होगा। सेनवेट मार्ग के अंतर्गत पूर्व की अवस्थाओं में अदा किए गए सभी उत्पाद शुल्कों के लिए क्रेडिट लिया जा सकता है। वैकल्पिक सेनवेट मार्ग के प्रयोजनों हेतु यह आवश्यक है कि प्रशुल्क अनुसूची में लागू उत्पाद शुल्क दरों को विनिर्दिष्ट किया जाए। शुद्ध सूती क्षेत्रक के लिए, धागा, कपड़ा, परिधान और सिले-सिलाए वस्त्रों पर एकसमान दर 4 प्रतिशत होगी। मिश्रित कपड़ा क्षेत्रक और शुद्ध गैर सूती क्षेत्रक के लिए एक समान दर 8 प्रतिशत होगी।

146. मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाखों हथकरघा बुनकरों तथा विद्युत करघा बुनकरों द्वारा इस नई व्यवस्था का स्वागत किया जाएगा। जहां तक मिश्रित मित्तों का संबंध है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे छूट वाली प्रणाली अपनाने के लिए मुक्त हैं परंतु यदि वे सेनवेट प्रणाली अपनाना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं तथा उन्हें पहले अदा किए गए सभी शुल्कों के लिए सेनवेट क्रेडिट का दावा करना चाहिए। गारमेंट निर्यातकों को इस नई व्यवस्था को एक उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। मुझे आशा है कि वस्त्रों के मूल्य कम होंगे तथा गारमेंट निर्यातक लाभ में रहेंगे। यदि उनकी कोई चिंताएं होंगी तो उन्हें वापसी अथवा डीईपीबी व्यवस्था के माध्यम से दूर कर दिया जाएगा।

147. समय बीतने के बाद यह संभव है कि हथकरघों तथा विद्युत करघों के कुछ निर्माता शुल्क की निम्न एकसमान दरों का लाभ उठाएंगे तथा सेनवेट प्रणाली का विकल्प चुनेंगे।

148. अब सेवा कर आता है वस्तुओं तथा सेवाओं के एकीकरण की दिशा में, मैं एक बड़ा कदम उठाना चाहता हूँ। तदनुसार, मैं सेवाकर तथा उत्पाद शुल्क संबंधी क्रेडिट का विस्तार वस्तुओं तथा सेवाओं पर भी करने का प्रस्ताव रखता हूँ। ऐसे विस्तार के राजस्व संबंधी प्रभाव को निष्क्रिय करने की दृष्टि से तथा औसत सेनवेट दर को ध्यान में रखते हुए मैं सेवा कर को 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

149. अभी तक 58 सेवाओं को कर दायरे में शामिल किया गया है। इस वर्ष मैं कुछ और सेवाओं को इस दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इन सेवाओं में व्यापार प्रदर्शनी सेवाएं; हवाई सेवाएं; परिवहन बुकिंग एजेंटों द्वारा प्रदत्त सेवाएं; वस्तुओं को वायुयान द्वारा भेजना; सर्वेक्षण और अन्वेषण सेवाएं, चुनाव निष्कर्ष सेवाएं; कापी राइट को छोड़कर बौद्धिक संपत्ति सेवाएं; वायदा संविदाओं के दलालों, पंडाल और शमियाना ठेकेदार तथा बाहरी स्थानों पर खाने पीने का प्रबंध करने वाले; स्वतंत्र टावी/रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता; वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण से संबंधित सेवाएं; तथा जोखिम प्रीमियम की सीमा तक जीवन बीमा सेवाएं शामिल हैं। मैं यह स्पष्ट

कर देना चाहता हूँ कि ट्रक मालिकों अथवा ट्रक प्रचालकों पर सेवा कर लगाए जाने का कोई इरादा नहीं है। और न ही, जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती मंत्री महोदय द्वारा भी स्पष्ट किया गया था, किसी बीमाकर्ता द्वारा संग्रहित प्रीमियम के बचत वाले हिस्से पर सेवा कर लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है।

150. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि कुछ मौजूदा कर-योग्य सेवाओं को पुनर्परिभाषित किया जाए ताकि समान श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सभी सेवा प्रदाताओं को कवर किया जा सके, लेकिन मैं इस भाषण में उसका विस्तारपूर्वक उल्लेख करना नहीं चाहता, कुछ कर योग्य सेवाओं के मामले में प्रदत्त रियायतों को हटाए जाने का प्रस्ताव है। सेवा कर का प्रशासन करदाताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जाएगा। मैं स्वतः निर्धारण के अनिवार्य प्रमाणन तथा अपंजीकरण के सम्बन्ध में अनिवार्य दंड की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

151. अन्त में, राष्ट्रीय साझा-न्यूनतम कार्यक्रम द्वारा आदेशित कर है जो सभी करों पर शिक्षा उपकर के रूप में है। मैं आयकर, निगम कर, उत्पाद शुल्कों, सीमा शुल्कों, तथा सेवाकर पर 2 प्रतिशत उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

152. मेरे कर प्रस्तावों के अलावा मैंने राजस्व के एक दूसरे स्रोत को भी देखा है। प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों, दोनों में भारी वसूली योग्य बकाया धनराशियाँ हैं। यहां तक की अविवादित बकाया धनराशियाँ भी काफी पर्याप्त हैं। अतः मैं यह मानता हूँ कि इस वर्ष में इस धनराशि को वसूल करने में समर्थ रहूंगा। एक विशेष बहुमुखी अभियान इस बकाया धनराशियों की वसूली के लिए चलाया जाएगा जिसके विवरणों की घोषणा बाद में की जाएगी।

153. प्रत्यक्ष करों पर मेरे कर प्रस्तावों से 2000 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होने की आशा की जाती है। अप्रत्यक्ष करों के मामले में वह मुख्यतः राजस्व के लिए निष्प्रभावी हैं।

XII. निष्कर्ष

154. अध्यक्ष महोदय। भारत सहित विश्व के देशों ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हमारी लक्ष्य प्राप्ति की तारीख सहस्राब्दि के अंत में नहीं है बल्कि वर्ष 2015 है। क्या हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पायेंगे? हमारे पास जो ग्यारह वर्ष शेष हैं उन्हीं में हमने अपने प्रारब्ध का निर्माण करना है। प्रगति हमेशा एक रेखीय पथ पर नहीं होती और न यह अवश्यभावी है। दो हजार वर्ष पहले संत तिरुवल्लुवर ने कहा था:-

अरन इयुक्कत्थु अल्लवई नीकि मारन इयुक्क
माणम उडयथु अरसु।

(वही अच्छे शासक हैं जो आचार एवं नैतिकता का पालन करते हैं, कोई अपराध नहीं करते और सम्मान एवं साहस के मार्ग पर चलते हैं)

यदि हम अपने प्रशासन को विचार एवं उमंग प्रदान कर सकें, सम्मान और साहस के मार्ग पर चल सकें तो भविष्य को खुशहाल बना सकते हैं। यह शताब्दी भारत की शताब्दी होगी।

155. महोदय, मैं इन शब्दों के साथ यह बजट सदन को प्रस्तुत करता हूँ।”

के. एस. मेनन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2004

F. No. 2(29) B(D)/2004.—The following is published for general information :—

“Budget 2004-2005

Speech of

P. Chidambaram

Minister of Finance

July 8, 2004

PART A

Mr. Speaker, Sir.

I. INTRODUCTION

1. I rise to present the budget for the year 2004-05.
2. Every five years, or sometimes sooner, the people of India speak in their collective voice. The message is usually unambiguous and clear. Elections 2004 were no different. The people's vote against one coalition – and the vote in favour of another coalition – was a vote for change. As the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, said in his address to the Nation two weeks ago, the people have sought “a change in the manner in which this country is run, a change in national priorities, and a change in the processes and focus of governance.” I shall make every effort to be true to that mandate.

**II. NATIONAL COMMON MINIMUM PROGRAMME:
THE GUIDING LIGHT**

3. The United Progressive Alliance (UPA) has given to itself, and to the people of this country, a Common Minimum Programme. The Government has since adopted it as the National Common Minimum Programme (NCMP). The programme spells out seven clear economic objectives:

- (1) maintaining a growth rate of 7 - 8 per cent per year for a sustained period;
- (2) providing universal access to quality basic education and health;
- (3) generating gainful employment in agriculture, manufacturing and services, and promoting investment;
- (4) assuring 100 days' employment to the breadwinner in each family at the minimum wage;

-
- (5) focusing on agriculture and infrastructure;
- (6) accelerating fiscal consolidation and reform; and
- (7) ensuring higher and more efficient fiscal devolution.

4. The UPA government began its journey in May this year. However, I may note that one-quarter of the year has elapsed and, by the time the Budget is passed and the President gives his assent to the Finance Bill, nearly one-half of the year will be over. There is also an Interim Budget left behind by my predecessor.

5. The Government has to shift gears; and even if we are able to do so quickly, it would leave us only about six months to achieve our objectives for this year. We have therefore decided to adopt an innovative approach. The Planning Commission has advised the ministries and departments to redefine their priorities and redraw their programmes in accordance with the NCMP. This will necessarily involve some changes in the allocations under each head of expenditure. Besides, new programmes or schemes may have to be launched, and old ones restructured. Under the circumstances, it was considered optimal to allow the ongoing programmes to continue until the Planning Commission completes an exhaustive review and reorients the expenditure pattern to conform to the NCMP objectives. One thing, however, is clear. The Plan resources made available in the Interim Budget will be insufficient. Hence, in addition to the Gross Budgetary Support (GBS) of Rs.135,071 crore provided in the Interim Budget, I propose to provide a sum of Rs.10,000 crore. This, and some other additional allocations, will raise total plan expenditure to Rs.145,590 crore in the Budget Estimates for 2004-05.

III. FRBM AND THE MACROECONOMIC BACKDROP

6. The Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) 2003 has streamlined the Budget presentation process. The Government has demonstrated its commitment to prudent fiscal and financial policies by notifying the Act and the Rules with effect from July 5, 2004. Along with the Budget, a medium-term fiscal policy statement, a fiscal policy strategy statement and a macroeconomic framework statement are being presented to the House.

7. Under the FRBM Act, I am obliged to wipe out the revenue deficit by 2007-08. However, the NCMP has proposed that we do so by 2008-09. In my view, 2008-09 is a more credible terminal year; it will also coincide with the term of this Government. Hence, I propose to move an amendment to this effect through the Finance Bill. I am committed to implementing the FRBM Act. The elimination of revenue deficit will open up fiscal space up to 3 per cent of GDP for enhanced public investment without undermining fiscal prudence.

8. The economic fundamentals appear strong and the balance of payments is robust. Although there are short term pressures on prices, the outlook for the

year is benign and the Government is fully alert. Growth will be sustained by increased production and value addition in agriculture, a marked improvement in industrial production, and continued buoyancy in the performance of the services sector.

9. The Government will follow a 5-year road map to achieve the NCMP objective of bringing about rapid growth with stability and equity. Sequencing the measures in an appropriate fashion and continuing the reform process, which ushered in the era of rapid growth, are the main challenges. The Government is committed to strike a fine balance among the three mutually reinforcing objectives of growth, stability and equity.

IV. ASSAULT ON POVERTY AND UNEMPLOYMENT

10. One of our greatest assets is our human resources, our people. Empowering the people, especially the poor, with universal access to education and health, and facilitating their full participation in the growth process through gainful employment, will enhance their welfare. It will also reinforce the growth process itself. This win-win strategy is the keystone of the economic policy framework of the Government.

Plan reorientation

11. I have the benefit of the wise counsel of the Prime Minister, Dr Manmohan Singh. In our scheme of things, the poor will have a first charge not only on the additional sum of Rs.10,000 crore of GBS that I propose to provide today, but also on the entire Plan funds that the Planning Commission will reallocate.

12. The poor want basic education for their children: we shall provide it, and we shall make sure that the child remains in school for at least eight years. We shall also make sure that the child is not hungry while she or he is at school. The poor want drinking water: we shall ensure that every habitation has an assured source of drinking water. The poor want basic health care, medicines at fair prices and a doctor within a reasonable distance: we shall ensure that the public health system has adequate human and financial resources to provide basic medical care. The poor want jobs for their children: we shall ensure that through higher investments, and through targeted intervention, jobs are available to them.

13. While the Planning Commission will make the final allocations, I may assure the House that crucial programmes such as Food for Work, Sarva Shiksha Abhiyan, Midday Cooked-Meal Scheme, basic health care, railway modernisation and safety, Accelerated Irrigation Benefit Programme, drinking water, investment in agriculture, Provision of Rural amenities in Urban Areas (PURA), roads, and science and technology, including bio-technology, will receive priority and will be provided with additional funds.

Antyodaya Anna Yojana

14. I propose to continue, and expand, the Antyodaya Anna Yojana. At present, 1.5 crore families are covered. These families are provided with 35 kg. of foodgrains per family per month at a highly subsidized price of Rs. 2 per kg. for wheat and Rs.3 per kg for rice. 20.76 lakh tonnes of rice and 17.48 lakh tonnes of wheat were distributed under the Scheme in 2003-04. In the current year, I propose to cover 2 crore families. I expect that the off-take of rice and wheat will increase. Consequently, the Antyodaya Anna Yojana will receive a subsidy of nearly Rs.3500 crore. A provision for this level of expenditure has been included in the allocation for food subsidy of Rs.25,800 crore.

Public distribution system

15. Fair price shops constitute the backbone of the food security system for the poor. We shall address the weaknesses in the system and strengthen public distribution. I shall return to this subject a little later.

Food for Work Programme

16. Investment and growth will create new job opportunities for our young men and women. Nevertheless, currently there is a need to ensure that unemployment does not take a heavy toll on the poor people. Work has begun on the National Employment Guarantee Act. The object is to guarantee 100 days of employment in a year to one able-bodied person in every poor household. The Bill will take into account the experience gained in Maharashtra. Government will also take care to avoid the pitfalls pointed out by responsible critics. My colleague, the Minister of Labour, expects that he would be able to introduce the Bill in Parliament shortly. Pending the enactment of the new law, I propose to launch a new Food for Work programme in 150 districts classified as most backward and identified as areas in immediate need of such a programme. Allocations under different schemes will be pulled together to support the Food for Work programme. There are substantial funds totaling over Rs.6000 crore under SGRY, SGSY, SJSRY, REGP and PMRY. Depending on the demand for such work, more funds will be allocated in the current year. I expect to increase the allocations substantially over the next four years. Special care will be taken in laying down the guidelines for the programme so that the money and labour expended result in durable and visible assets benefiting the whole community.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes

17. The welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is close to my heart. The allocation for programmes concerning the Scheduled Castes is Rs.1180 crore (an increase from Rs.1137 crore) and for Scheduled Tribes is Rs.1146 crore (an increase from Rs.1087 crore). Other plan schemes such as SGSY, SGRY and IAY also contain specific reservations for beneficiaries belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The reservations range from 50 per cent to 60 per cent.

Minorities

18. Particular attention will be paid to the welfare, especially education, of the minorities. Hence, an additional allocation of Rs.50 crore has been made for the National Minorities Development and Finance Corporation.

Self-help groups

19. Microfinance initiatives are a cost-effective way to take the banking system to the poor. The Self-Help Group (SHG) – bank linkage programme, initiated in 1992, has come a long way. Until March 31, 2004, 1.67 crore families had benefited through 10.79 lakh SHGs financed by banks. While the SHG concept will be promoted vigorously, I am of the view that matured SHGs may be in a position to graduate from consumption or production credit to starting micro-enterprises. An indicative target of credit linking 5.85 lakh SHGs during the period up to March 31, 2007 has been set for NABARD, SIDBI, banks and other agencies.

V. THRUST AREAS

20. Before I deal with other areas of concern on which the Budget will have an impact, let me give you a snapshot of the goals that I have set for myself :

- Doubling agricultural credit in three years, accelerating the completion of irrigation projects and investing in rural infrastructure;
- Providing farm insurance and livestock insurance;
- Improving agricultural product markets, and promoting agri-businesses;
- Drinking water for all;
- Expanding water harvesting, watershed development and minor-irrigation and micro-irrigation schemes;
- Enhancing investment in industry – public and private, domestic and foreign – to create new jobs;
- Creating space for small-scale industry to thrive and grow;
- Electricity for all;
- Universal access to telecommunication facilities;
- More housing for the poor;
- Access to medical care through health insurance; and
- Encouraging savings, and protecting the savings of senior citizens;

21. I believe that the key to growth is investment – public and private, domestic and foreign. It is therefore my intention to considerably enhance investment in all sectors of the economy. However, fiscal prudence and financial discipline

will remain the overarching objective. I shall also take into account the availability of resources and the absorptive capacity of various sectors.

VI. EDUCATION AND HEALTH

Education

22. In my scheme of things, no issue enjoys a higher priority than providing basic education to all children. The NCMP mandates Government to levy an education cess. I propose to levy a cess of 2 per cent. The new cess will yield about Rs.4000 - 5000 crore in a full year. The whole of the amount collected as cess will be earmarked for education, which will naturally include providing a nutritious cooked midday meal. If primary education and the nutritious cooked meal scheme can work hand in hand, I believe there will be a new dawn for the poor children of India.

23. I am concerned about the quality of technical education³ in the country. Lest I be misunderstood, I am not referring to the IITs but to the ITIs. ITIs are the training ground for skilled manpower. The skills imparted by ITIs must keep pace with the technological demands of industry and the expanding universe of knowledge. There is only one benchmark for our technicians – and that is the world standard. In order to produce technicians of world standard, Government proposes to launch a programme in the Central sector to upgrade 500 ITIs over the next 5 years at the rate of 100 ITIs a year. Appropriate infrastructure and equipment will be provided, the syllabi will be upgraded and new trades will be introduced. This is an area where I welcome Chambers of Commerce and Industry to join hands with the Government and create a public-private partnership model for designing and implementing the scheme. The selection of the ITIs will be done in consultation with the State Governments.

24. An education loan scheme has been in operation since April 2001 under which loans up to Rs.7.50 lakh and Rs.15 lakh are available for professional courses within the country and abroad, respectively. The requirement of collateral was dispensed with for loans up to Rs.4 lakh. I am happy to say that commercial banks have now agreed to waive the need for collateral for loans up to Rs.7.5 lakh, if a satisfactory guarantee is provided on behalf of the student. Thus, no student admitted to any professional course, including courses in IITs, IIMs and medical colleges, will be deprived of the opportunity to study because of lack of funds.

Health

25. Access to medical care is not easily available to the poor. The Universal Health Insurance Scheme (UHS) now in operation is skewed in favour of the non-poor. As a result, only a very small number of families below the poverty line (BPL) – actually 11,408 till May, 2004 – have been covered. Although the premiums are low, BPL families seem to avoid the scheme due to their inability to pay the premium. In its present design, the scheme may not be sustainable.

I, therefore, propose to redesign the scheme and make it exclusive for persons and families below the poverty line. The revised premium would be Rs.165 for individuals, Rs.248 for a family of five and Rs.330 for a family of seven, without any reduction in benefits. To offset the reduction in premium, I propose to enhance the premium subsidy from Rs.100 at present to Rs.200 for an individual, Rs.300 for a family of five and Rs.400 for a family of seven. The cost to the exchequer will be Rs.40 crore in a full year. If the money is fully spent, the number insured will rise to about 10 lakh.

26. In addition to the above, I propose to introduce a new Group Health Insurance Scheme through public sector non-life insurance companies. The insured will be members of Self-Help Groups (SHGs) and other credit linked groups (CLGs) who avail of loans from banks or cooperative institutions. Under the group health insurance scheme, the premium will be Rs.120 per person, but the insurance cover would be for a sum of Rs.10,000.

27. The NCMP also rightly emphasizes the need for an accelerated AIDS control programme. Bold and determined efforts need to be made to achieve zero-level growth of HIV/AIDS. These will include improved surveillance through the setting up of more sentinel sites and use of primary health centres to monitor HIV/AIDS, public awareness campaigns, promotion of safe sex through the use of condoms, prevention of drug abuse and distribution of disposable syringes. The allocation for prevention and control of HIV/AIDS is Rs. 259 crore.

VII. AGRICULTURE AND THE RURAL ECONOMY

28. Boosting agricultural growth through diversification and development of agro-processing is one of the objectives of the NCMP. The Prime Minister, in his address to the Nation on June 24, 2004 promised a "New Deal" for rural India. This New Deal is not only essential for rural development and welfare, but also essential for achieving sustained overall annual growth of 7-8 per cent and generating employment.

29. The agriculture sector requires massive investments. Such investments have to be through credit-enabled private investment and enhanced public investment. I also intend to use fiscal instruments to boost investment in agriculture.

Credit

30. It is my intention to double the flow of agricultural credit in three years. We have made a beginning by announcing a comprehensive policy on agricultural credit on June 18, 2004. The policy has been received well and will be fine-tuned, if necessary.

31. Government has entrusted the implementation of the policy to the public sector and private sector banks, the regional rural banks (RRBs) and the cooperative banks.

32. Each RRB has a sponsor bank. I propose to hold each sponsor bank squarely accountable for the performance of RRBs under its control. RRBs that adopt a new governance standard and that abide by the prudential regulations will qualify for receiving funds from the Government for their restructuring.

33. The third arm for delivering farm credit is the cooperative banking system. Unless cooperative banks are healthy and creditworthy, it would not be possible to reach credit to every farmer in need of credit. The situation is grave. In order to find a durable solution, I propose to appoint a Task Force to examine the reforms required in the cooperative banking system including the appropriate regulatory regime. The Task Force will be requested to act with all deliberate speed and submit its report by October 31, 2004.

Irrigation, Rural Infrastructure

34. The Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) was introduced in 1996-97 and was allotted large funds year after year. Yet, out of 178 large and medium irrigation projects that were identified, only 28 have been completed. The programme is being restructured. Truly last mile projects that can be completed by March 2005 will be given overriding priority, and other projects that can be completed by March 2006 will also be taken up in the current year. Next year we shall move the goal-post to March 2007, the year after to March 2008, and so on. I have provided a sum of Rs.2800 crore to the AIBP this year.

35. The Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) was established in NABARD in 1994-95. Five months ago, a decision was taken to close the RIDF and establish, in its place, another Fund with slightly different objectives. Many State Governments and many honourable Members have opposed the closure of RIDF. In deference to their wishes, and in tune with my own thinking, I have decided to revive the RIDF. RIDF's guidelines have been revised, and a corpus of Rs.8000 crore will be provided for RIDF during 2004-05.

Restoring water bodies

36. I now turn to one of my big dreams. Water is the lifeline of civilization. We have been warned that the biggest crisis that the world will face in the 21st century will be the crisis of water. Water is indeed a renewable resource but, in any given year, it is not inexhaustible. The crisis of water has affected the lives of millions of our fellow citizens. In some cities, whole households keep awake to receive one or two buckets of water well past midnight. In rural areas, the girl child is often pulled out of school in order to fetch water. I am deeply concerned about the impending crisis. I therefore propose an ambitious scheme. Through the ages, Indian agriculture has been sustained by natural and man-made water bodies such as lakes, tanks, ponds and similar structures. It has been estimated that there are more than a million such structures and about 500,000 are used for irrigation. Many of them have fallen into disuse. Many of them have accumulated silt. Many require urgent repairs.

37. I therefore propose to launch a massive scheme to repair, renovate and restore all the water bodies that are directly linked to agriculture. In the current year, we shall begin with pilot projects in at least five districts, and we shall select at least one district in each of the five regions of the country. The estimated cost is Rs.100 crore. Funds for the five pilot projects will be drawn from existing programmes such as SGRY, PMGJSY, DPAP, DDP and IWDP. Once the pilot projects are completed and validated, Government will launch the National Water Resources Development Project and complete it over a period of 7 to 10 years.

38. Funds will not be a constraint for implementing the Project. For instance, Life Insurance Corporation of India invests, on an average, Rs.3000 crore per year in water-related programmes. I also intend to pose this Project to multilateral agencies for funding. It is my hope that by the beginning of the next decade all water bodies in India will be restored to their original glory and that the storage capacity of these water bodies will be augmented by at least 100 per cent.

Water harvesting

39. Water harvesting schemes, specific to an area or village, have been found to be extremely useful. Such schemes are supported by a number of credit institutions. However, farmers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes rarely benefit from such schemes. In order to help these farmers, Government will launch a nationwide water harvesting scheme. The scheme will cover one lakh irrigation units at an average cost of Rs.20,000 per unit. NABARD will lend the money on easy terms and no margin money will be charged from the borrower. Government will provide a 50 per cent capital subsidy through NABARD, and the estimate for the scheme is Rs.100 crore.

Flood control

40. Thousands of lives and thousands of head of cattle are lost every year due to floods. Floods are perennial in States like Assam, West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh. The NCMP envisages full Central support to flood control works in inter-State rivers and international rivers. The Brahmaputra Board has prepared a plan for anti-erosion and flood control works in the Brahmaputra and Barak valleys. A programme of flood control and anti-erosion will be launched in the current year. A similar programme is being implemented in the Ganga-basin States of Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal. Rs.30 crore has been allotted in the current year and additional funds will be provided to keep pace with the progress of works.

Diversification

41. India is self-sufficient in wheat and paddy but deficient in other agricultural produce. The time has come to encourage our farmers to diversify into areas such as horticulture, floriculture and oilseeds. The Anand model has been a great success in milk and milk products. Government proposes to launch a

National Horticulture Mission. The goal is to double horticulture production from the current level of 150 million tonnes to 300 million tonnes by 2011-12. I invite States to join hands with the Government in launching this mission. One of the steps that States will be encouraged to take is to emulate the Anand model and establish a State Level Cooperative Society for promoting horticulture.

42. Oilseeds is another critical area. Last year, we produced 25 million tonnes of oilseeds, but we also imported US\$ 2.5 billion of edible oil. Government will facilitate farmers to diversify into oilseeds by promoting superior seed-technology and through an appropriate policy of price support.

43. India must become a single market for all products, particularly agricultural produce. The existing Acts governing agricultural produce marketing committees have outlived their utility. The Government has circulated a model law. So far, ten States have initiated legal or administrative action for 'direct marketing' and 'contract farming' arrangements in line with the model law. I urge all States to enact the model law at an early date.

Research and Development

44. Agricultural research and development is an area which deserves special attention. The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) is a beneficiary of the scheme under which every commercial rupee earned by ICAR, incrementally, is matched by another rupee from the Budget. Besides, ICAR receives funds from the Technology Development Board in respect of projects that are commercially viable. Agricultural research must be expanded rapidly to new frontiers such as bio-technology, vaccines and diagnostics. There must be a special focus on farming in drylands and unirrigated areas. The allocation for 2004-05 is Rs.1000 crore (which is an increase from Rs.775 crore in BE 2003-04), and I propose to make further allocations during the course of the year.

Agri-business

45. The Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC) was set up in 1994. Although SFAC started functioning from 1998, its corpus stands at a meagre Rs.10.95 crore. In my view, SFAC should provide venture capital to projects and must be run, preferably by a banker, on purely business lines. The MS Swaminathan Research Foundation has identified 13 districts where there is a huge potential for agri-businesses and an appetite for investment of nearly Rs.170 crore. The Ministry of Agriculture has initiated action to improve the governance of SFAC, including the appointment of a banker as the chief executive. For my part, I propose to provide the necessary additional capital that SFAC will require to aggressively promote agri-businesses.

Risk mitigation

46. The Agricultural Insurance Company (AIC) was incorporated in December 2002. The National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) which insures the yield or crop is in operation since Rabi 1999-2000. AIC is redesigning the

scheme. We shall continue with the scheme and make another evaluation. Meanwhile, a pilot scheme insuring farm income (as opposed to crop) has been launched in 19 districts across 12 States during Rabi 2003-04. Government has decided to extend the scheme to Kharif 2004 in order to assess its feasibility. I wish to add that a weather insurance scheme appears to be more promising, at least in the design. AIC is introducing the scheme on a trial basis in 20 rain gauge stations in the current crop season. It is difficult to tell at this stage which of the three schemes will be successful. Agricultural insurance as well as livestock insurance are complex products and have to be designed with care. I wish to re-affirm Government's commitment to provide insurance cover to farming and livestock.

VIII. INFRASTRUCTURE

47. Sustainable growth depends upon the availability of efficient infrastructure. Government is committed to removing the inadequacies in infrastructure facilities through a mix of policy and fiscal measures.

Inter-Institutional Group

48. An Inter-Institutional Group in the power sector has succeeded in bringing 6 power projects to financial closure. Another 10 projects are on the verge of achieving financial closure. The concept can be extended to some other infrastructure sectors. I am glad to announce that IDBI, IDFC, ICICI Bank, SBI, LIC, Bank of Baroda and Punjab National Bank have formed an Inter-Institutional Group (IIG). They will pool their resources on a callable basis, and a sum of Rs.40,000 crore will be made available as and when necessary. The IIG will ensure speedy conclusion of loan agreements and implementation of infrastructure projects. Initially, airports, seaports and tourism will be the target sectors of the IIG.

Water supply

49. The Rajiv Gandhi Drinking Water Mission was intended to be implemented in the mission mode. In recent years, however, new programmes have sprung up obscuring the original mission. More than 75,000 habitations are yet to be provided adequate drinking water. Government intends to bring all drinking water schemes under the umbrella of the Rajiv Gandhi Drinking Water Mission.

50. The Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) has been allocated Rs.2610 crore in the current year. It will focus on renewal of water sources and on serving uncovered and partially covered habitations. Panchayati raj institutions will be encouraged to plan, implement, own, operate and maintain the rural water supply schemes in consultation with the State Governments. Funds will be devolved on Panchayati raj institutions to implement the ARWSP.

51. Likewise, the Urban Water Supply Programme is in operation in urban areas. 2151 towns qualify for consideration under the programme. In the current year a provision of Rs.151.25 crore has been made.

52. The city of Chennai and other cities suffer from acute scarcity of drinking water. It is proposed to install the first large desalination plant near Chennai in the State sector, and more such plants will be installed along the Coromandel coast. A desalination plant with a capacity of 300 million litres per day (MLD) is estimated to cost Rs.1000 crore, and there will be other costs for transmission pipelines and a captive power plant. It is proposed to implement the project through public-private partnership.

Sethusamudram Ship Canal Project

53. The Sethusamudram Ship Canal Project is a longstanding demand – nay dream – of the people of peninsular India. I am happy to inform the House that the Environmental Impact Assessment study of the project has been completed by the National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur. NEERI is now preparing the techno-economic feasibility report and the report is expected to be submitted shortly. The Ministry of Shipping proposes to establish a special purpose vehicle (SPV). The SPV will raise funds for the project and Government will participate in the funding through a mix of equity support and debt-guarantee.

International Container Transshipment Terminal (ICTT) at Vallarpadam

54. Government attaches high priority to the development and expansion of port infrastructure. Presently, because of inadequate draft and cargo handling infrastructure, and partly due to locational disadvantages, mainline vessels often skip Indian ports. Containers from India are carried to their final destination after transshipment at Colombo, Dubai and other neighbouring ports. Kochi has locational advantages compared to other major Indian ports since it is closer to the main sea routes. Government will facilitate the construction of an International Container Transshipment Terminal (ICTT) at Vallarpadam in Kochi port on Build, Operate and Transfer (BOT) basis.

Rural housing

55. Indira Awas Yojana (IAY) has been the main instrument to provide housing to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as well as to the non-SC/ST rural poor. Built into IAY is a credit-cum-subsidy scheme for rural households. A subsidy upto Rs.10,000 and loan upto Rs.40,000 are provided to eligible households. The allocation for IAY in BE 2003-04 was Rs.1710 crore. In the current year, I propose to raise the allocation to Rs.2247 crore and, if more money is needed, it will be found within the enhanced Plan outlay.

56. In order to complement IAY, the Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme was launched in August 1997 to give a boost to rural housing. The response has been encouraging, and 10.26 lakh dwelling units have been financed so far. However, the number appears to have stagnated at about 180,000 per year in the last three years. The scheme deserves a further stimulus. I am happy to announce that the National Housing Bank has offered to reduce the rate of refinance by 25 basis points this year. RBI has agreed to revise the norms of re-payment for rural housing loans by banks, so that the instalments

coincide with crop cycles. A major impediment to credit for rural housing is absence of proper title to the land. The Government of West Bengal has made a law to simplify the creation of security. It appears to me that the law deserves to be emulated by other States. With these changes, I believe it is possible to set a higher target of 250,000 rural housing units per year.

IX. INDUSTRY

57. It is my goal to make the environment in India attractive for investors. In order to achieve that goal, I propose to establish an Investment Commission. The Commission will have the broad authority of the Government to engage, discuss with and invite domestic and foreign businesses to invest in India. It will be chaired by an eminent person. The Foreign Investment Promotion Board (FIPB) has played a useful role, and even now it serves as a one-stop centre for securing the nod of different ministries and departments to a proposed investment. Government believes that many of the functions of FIPB could be put on the automatic route, and leave FIPB as a one-stop service centre and facilitator. The function of wooing domestic and foreign investors will be performed by the proposed Investment Commission.

58. Government proposes to set up a National Manufacturing Competitiveness Council. The Council will be a continuing forum for policy dialogue to energise and sustain the growth of manufacturing industries. The Council will be asked to suggest measures for enhancing competitiveness in the manufacturing sector. The Council may also recommend industry-specific or sector-specific policy initiatives to enhance competitiveness.

59. Foreign Direct Investment (FDI) has the potential to add a competitive edge, especially in the industrial sector. The NCMP declares that FDI will continue to be encouraged and actively sought, particularly in areas of infrastructure, high technology and exports. Three sectors of the economy fully meet this description. They are telecommunications, civil aviation and insurance. There is an urgent need for infusing huge amounts of capital in these sectors. I, therefore, propose to raise the sectoral cap for FDI in telecommunications from 49 per cent to 74 per cent; in civil aviation from 40 per cent to 49 per cent; and in insurance from 26 per cent to 49 per cent.

Capital Markets

60. Government is committed to the orderly development and functioning of the capital markets. A number of steps have been taken to broaden and deepen the capital markets as well as to strengthen the regulatory regime. There are some signs that retail investors are returning to the capital market. Foreign Institutional Investors (FIIs) have shown a marked preference for India over other emerging markets. In order to carry forward the process of making the Indian capital market strong and attractive, I propose to –

- Make the procedures for registration and operations simpler and quicker for FIIs;

- Raise the investment ceiling for FIIs in debt funds from US\$ 1 billion to US\$ 1.75 billion;
- Allow banks with strong risk management systems greater latitude in their exposure to the capital market;
- Create an alternative trading platform for small and medium enterprises (SMEs) to raise equity and debt from the capital market; and
- Initiate steps to integrate the commodities markets and the securities markets.

RBI and SEBI will announce the necessary measures in respect of these matters. I am also happy to announce that SEBI has been able to resolve the longstanding issue of brokers' fees, and brokers may expect an announcement shortly.

61. Many genuine foreign institutional investors (FIIs) are professional bodies of asset managers and financial analysts who can enhance the flow of equity capital and lend depth to the capital markets. An inter-ministerial committee has recommended liberalization of FII limits in certain specified sectors. I propose to examine and implement these recommendations in consultation with the Ministries concerned.

Public sector

62. The NCMP has declared the Government's policy on public sector enterprises (PSEs). While sick or ailing public sector enterprises have stirred a debate, not enough attention is paid to the healthy PSEs. I am happy to announce that in 2004-05 the Government will provide equity support of Rs.14,194 crore and loans of Rs.2,132 crore to Central PSEs (including Railways). Major investments will be made in PSEs falling in the sectors of power, telecommunications, railways, roads, petroleum, coal and civil aviation. I am sure Hon'ble Members will appreciate the deep commitment of Government to a strong and effective public sector operating in a competitive environment.

63. There is, of course, another side to the public sector. This side is beset with problems, and we must address them with responsibility and courage. Disinvestment and privatization are useful economic tools. We will selectively employ these tools, consistent with the declared policy. As a first step, I propose to establish a Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE). The Board will advise the Government on the measures to be taken to restructure PSEs, including cases where disinvestment or closure or sale is justified.

64. One of our Navaratna companies, NTPC, has filed a prospectus with SEBI to raise capital through a public issue. Consequently, Government's holding in NTPC will be marginally diluted. In order to extract value for its holding and to compensate the effect of dilution, Government intends to piggy-back on the public issue of NTPC and disinvest approximately five per cent of its holding.

This and some other cases which are under examination are expected to yield a sum of Rs.4000 crore in the current year. While the disinvestment revenues will be part of the Consolidated Fund of India, I shall, while presenting the Budget for 2005-06, report to the House the manner in which the said revenues have been or will be applied for specified social sector schemes.

65. The NCMP contains clear policy guidelines regarding disinvestment in PSEs. As long as Government retains control over the PSE, and its public sector character is not affected, Government may dilute its equity and raise resources to meet the social needs of the people. I propose to ask the BRPSE to examine each case objectively and make recommendations on disinvestment, consistent with the NCMP.

66. I am also happy to announce that I have taken the business of restructuring quite seriously. Hindustan Antibiotics Limited will be given financial support for restructuring. A rescue package has been worked out for Indian Telephone Industries (ITI), and ITI will be given Rs.508 crore to remain out of the net of the BIFR.

Small scale industry

67. Small scale industry is, and must be regarded as, an engine of growth. At the same time SSI units must also be given the space to grow into medium enterprises. World over, policies are devised to meet the requirements of small and medium enterprises (SME). Keeping in mind the twin objectives, the Ministry of Small Scale Industry has identified 85 items that can be safely taken out of the reserved list. Furthermore, it is felt that technology upgradation of SSI units is the most urgent requirement to do business in a competitive environment. I have reviewed the Capital Subsidy Scheme, and I propose to raise the ceiling for loans under the scheme from Rs.40 lakh to Rs.1 crore. The rate of subsidy will also be raised from 12 per cent to 15 per cent. The scope of the scheme will be enlarged by adding more sub-sectors and technologies eligible for assistance. SSI units will be encouraged to obtain credit rating. With these measures, I expect that many more SSI units will benefit from the restructured scheme. A provision of Rs. 135.24 crore has been made for "Promotion of SSI Schemes", and within that amount funds will be found for the Capital Subsidy Scheme.

Regeneration of traditional industries

68. Some of our traditional industries, namely coir, handloom, handicrafts, sericulture, leather, pottery and other cottage industries not only contain great potential for growth and exports, but are integral for the maintenance of our cultural heritage. Accordingly, a Fund for the Regeneration of Traditional Industries, with an initial allocation of Rs.100 crore will be set up. The details, including mechanism for utilization of the fund will be worked out in consultation with the industries concerned.

X. OTHER PROPOSALS

VAT

69. Value-added tax is a tax that has been tested and tried, and found beneficial throughout the world. The country needs a modern and efficient trade tax system that incorporates the international best practices. At the June 18, 2004 meeting of the Empowered Committee of State Finance Ministers, to which all Finance Ministers were invited, and chaired by my distinguished friend Dr. Asim Das Gupta, there was a broad consensus among the States to implement VAT. April 1, 2005 has been set as the date for implementation. I welcome the decision and warmly congratulate the State Governments. I urge all States that have not yet passed the relevant VAT legislation to do so before the end of 2004. International experience, as well as the experience of the State of Haryana, suggests that VAT will lead to an increase in revenue and not a loss in revenue. Nevertheless, in order to give comfort to the States, I propose to evolve a formula for determining the compensation for the loss of revenue, if any. I have offered the States the services of a Technical Experts Committee. The Committee will work with the States closely, and help them move steadily towards the stage of implementation.

Pension Reform

70. A 'defined contribution' pension scheme has been introduced with effect from January 1, 2004 for the Central Government employees recruited on or after that date. A suitable legislation to provide a regulatory framework for the scheme will be introduced in Parliament.

Export promotion

71. My colleague, the Minister of Commerce and Industry, will place before Parliament by the end of this month a new trade policy. Government is of the view that Special Economic Zones (SEZs) are growth engines that can boost manufacturing, exports and employment. The private sector has shown considerable interest in the development of SEZs. Five SEZs have started functioning. SEZs require a special fiscal and regulatory regime. The Commerce Minister will, shortly, introduce a Bill for regulating Special Economic Zones, and it is my belief that the passing of such a law would be a significant milestone in our quest to become a major hub for manufacturing and exports.

Securitisation Act

72. The constitutional validity of the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 has been upheld by the Supreme Court, except Sub-Section (2) of Section 17. In the wake of this judgement, many banks have pointed out practical difficulties likely to arise in speeding up the recovery of non-performing assets. It is proposed to amend the relevant provisions of the Act to appropriately address the Supreme Court's concerns regarding a fair deal to borrowers while, at the same time, ensuring that the recovery process is not delayed or hampered.

Related amendments to the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, if necessary, will also be made.

Interest Rates

73. The Central Government has saved considerably on interest on fresh borrowings because of moderate interest rates. The States were also able to borrow at lower rates and swap old high cost loans. Since 2002, States have benefited to the extent of nearly Rs.2500 crore through the debt swap scheme. While borrowers are benefited by moderate interest rates, there is a need to boost savings and to protect the savers. I am convinced that, in the larger interests of the country, we should maintain a benign interest rate regime that appropriately balances the legitimate claims of the savers and borrowers.

74. I believe that all interest rates should be aligned to the market, save for one or two exceptions. There is a need for a savings instrument that will give a return to senior citizens which is above the market-determined rate. There is also a need for an instrument that will provide a risk-free avenue for all citizens to save for a longer term, and such an instrument should bear a slightly higher rate of interest. Balancing these considerations, I do not propose to make any change in the existing rates of interest on small savings instruments. Consequently, PPF, GPF and the Special Deposit Scheme will attract 8 per cent interest this year. For senior citizens, I propose to introduce a new scheme called the Senior Citizens Savings Scheme offering an interest rate of 9 per cent per annum. For all other citizens, I propose to continue the Government Savings bond which will carry an interest rate of 8 per cent per annum. The Varishta Pension Bima Yojana may no longer be necessary since the new savings scheme will cover the senior citizens adequately.

Reform of Public Distribution System

75. In the Tenth Plan document, the Planning Commission had suggested that a system of distributing food stamps should be tested on a pilot basis. Every eligible family will be entitled to collect its monthly quota of food stamps from a designated distribution centre, and such stamps could then be used to buy foodgrains from any food shop. I propose to introduce a pilot scheme for distributing food stamps, instead of distributing food through fair price shops, in two or three contiguous districts in a selected State. I sincerely hope that one of the States will come forward to associate with the Central Government in this experiment.

Gender budgeting

76. Women's groups have met me and urged me to consider gender budgeting. This means that the budget data should be presented in a manner that the gender sensitivities of the budgetary allocations are clearly highlighted. An expert group on "Classification System of Government Transactions" has submitted its report on July 6, 2004. It has recommended appropriate systems for data collection and representation in the budget. The group has also recommended introduction of periodic benefit-incidence analysis. Government

will examine the recommendations, and I hope it will be possible for me to implement some of them in the Budget for 2005-06.

Subsidies

77. Seven years ago, I placed before Parliament the first paper on subsidies. The NCMP pledges that all subsidies will be targeted sharply at the poor and truly needy like small and marginal farmers, farm labour and the urban poor. I have asked the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) to prepare a blue print to accomplish these objectives. I expect to place the report before the House in the next session of Parliament.

States' Finances

78. In order to support the States, a substantial proportion of the taxes raised by the Central Government is transferred to the States. Besides, the Central Government extends loans to the States. In the light of the Budget Estimates for the current year, I am happy to report that the States' share of Union taxes and duties will increase to Rs.82,227 crore from Rs.63,758 crore in BE 2003-04. We are helping the States in other ways too. One of them is the Debt Swap Scheme. I propose to extend the facility of debt swap by allowing States to raise fresh loans and repay their old high-cost loans to NABARD and some other agencies. I also propose to consult the States on allowing them to increase their open market borrowings and reduce their dependence on loans from the Central Government. I shall also consider passing on external loans to the States on a back-to-back basis.

79. We are moving in the direction of empowering the States through devolution of larger resources. It is my fervent hope that States will accept the obligation to observe fiscal prudence and financial discipline.

80. Loans given by the Central Government to States carried an interest rate of 12.5 per cent. In 2003-04, the rate was reduced to 10.5 per cent. I am happy to announce a further reduction. Loans to the States will now bear an interest rate of 9 per cent with effect from April 1, 2004. States are expected to benefit to the tune of Rs.375 crore this year alone.

Special Economic Packages

81. The NCMP promises that special economic packages for Bihar, Jammu & Kashmir and the North Eastern States, announced in the past, will be implemented expeditiously. Bihar, for example, has a number of projects pending for a long time, including projects in power, roads, drainage and rehabilitation of displaced persons. I would like to assure the House that Bihar will be assisted through the Rashtriya Sam Vikas Yojana. A provision of Rs.3225 crore has been made for the present and, if necessary, this sum will be augmented.

North Eastern Region (NER)

82. The Government is committed to the speedy development of the North-Eastern States and Sikkim. Accordingly, all Ministries and Departments have

been mandated to allocate at least 10 per cent of their Plan budget for schemes and programmes in the NER. This amounts to an allocation of Rs.5823 crore to be spent in the NER. The amount remaining unspent from this 10 per cent allocation is transferred to a non-lapsable Central pool of resources for development of the NER. In the current year, Rs.650 crore have been provided from the Central pool of resources for specific projects and schemes in this region, up from Rs.550 crore in 2003-04.

Jammu & Kashmir

83. The Government will provide special assistance to the State of Jammu & Kashmir to have a reasonable Plan size. It will also provide financial support for the long pending Baglihar project. The Government has also agreed to provide a grant of Rs.300 crore to the State to ensure smooth switch-over from the current overdraft arrangement with the Bank of Jammu & Kashmir to the Ways & Means scheme of the RBI.

Backward States' Commission

84. NCMP envisages the creation of a Backward States Grant Commission to be used for creating productive assets in such States. It also envisages that all non-statutory resource transfers from the Central Government will be weighed in favour of poor and backward States, but with performance parameters as well.

85. I am happy to announce that the Government will set up a Backward States Grant Fund with a corpus of Rs.25,000 crore to be provided over a period of five years. While the existing Backward Districts Initiative Scheme with an annual outlay of about Rs.1,800 crore will be merged into this Grant Fund, the balance amount required for the annual contribution of Rs.5,000 crore will be earmarked from out of the total Central support to the Plan. It is expected that this will enable taking up social and physical infrastructure programmes in the poorest and most backward districts in the country within a given time frame. The Fund will become operational from the financial year 2005-06. Further details will be worked out in consultation with the Planning Commission.

Defence modernization

86. As promised in the NCMP, the Government is determined to eliminate all delays in the modernization of the Defence Forces. Having regard to the trend of defence capital expenditure in recent years, it has become necessary to make a higher allocation this year. Accordingly, I propose to increase the allocation for Defence to Rs.77,000 crore (as against Rs.65,300 crore in BE 2003-04) which includes an allocation for capital expenditure of Rs.33,483 crore (as against Rs.20,953 crore in BE 2003-04).

Budget Estimates for 2004-2005

87. Now, I turn to the budget estimates for the current year.

Plan expenditure

88. While preparing the Budget, I found that there is a plethora of Plan schemes. The number, the variety and even the acronyms under which these schemes are known are mind-boggling. I also found that there are many schemes with more or less the same objectives. In some cases, all the schemes were located in one ministry or department; in other cases, they were distributed among different ministries or departments. Plan schemes can be broadly divided into three categories – Central Sector, State Sector and Centrally Sponsored Schemes. The NCMP requires that all Centrally Sponsored Schemes, except national priority areas like family planning, shall be transferred to the States. Fortunately, a new Planning Commission is in place, and I am confident that the Planning Commission will bring some order into the tangled web of schemes.

89. Plan expenditure for 2004-05 is estimated at Rs.145,590 crore as against Rs.122,149 crore in the provisional actuals for 2003-04. While there is an increase in plan revenue expenditure from Rs.78,537 crore in 2003-04 to Rs.91,843 crore, there is an even sharper and welcome increase in plan capital expenditure from Rs.43,612 crore in 2003-04 to Rs.53,747 crore.

Non-plan Expenditure

90. Non-plan expenditure in 2004-05 is estimated to be Rs.332,239 crore, lower than Rs.349,787 crore in the provisional actuals for 2003-04 which includes capital expenditure of Rs.46,211 crore on repayment to the National Small Savings Fund. The increase in non-plan expenditure from the interim Budget is mainly on account of capital expenditure in defence (Rs.11,000 crore), and assistance to Indian Telephone Industries Ltd.

Revenue Deficit and Fiscal Deficit

91. Mr. Speaker, Sir, in the Budget Estimates for 2004-05, the total expenditure is estimated at Rs.477,829 crore, of which Rs.145,590 crore is for Plan and Rs.332,239 crore for non-Plan. I estimate total revenue receipts of the Central Government at Rs.309,322 crore and the revenue expenditure at Rs.385,493 crore. Consequently, the revenue deficit is estimated at Rs.76,171 crore equivalent to 2.5 per cent of GDP, which is one percentage point below the corresponding estimate of 3.5 per cent of GDP in 2003-04 (according to the provisional actuals). The fiscal deficit is estimated at Rs.137,407 crore, which is 4.4 per cent of the estimated GDP.

2106 GI/2004-7

PART B**XI. TAX PROPOSALS**

92. I shall now deal with my tax proposals.

93. Taxation is a key tool of fiscal policy. The NCMP has promised that "tax rates will be stable and conducive to growth, compliance and investment". Thanks to policies initiated in the 1990s, direct tax rates are now moderate and require only fine tuning from time to time. Indirect taxes have also been moderated through a calibrated reduction in customs and excise duties. The proportion of direct tax revenues to GDP has increased from 1.9 per cent in 1990-91 to 3.8 per cent in 2003-04. As expected, the proportion of indirect tax revenues to GDP has declined from 7.9 per cent in 1990-91, but the decline has been rather sharp with the proportion at 5.3 per cent in 2003-04. The weak spot is central excise. Excise revenues are stuck, rather stubbornly, at around 3.3 per cent of GDP. While reduction in excise duty rates partly accounts for this situation, the expansion of the manufacturing industry ought to have given us larger revenues.

94. Through my policies on taxation, I wish to signal that we remain committed to moderation and stability in tax rates; that we remain committed to increasing revenues from direct taxes and excise duties; and that we remain committed to expanding the service tax net because the services sector accounts for 51 per cent of GDP. I shall also use tax policies to provide incentives to certain kinds of investment and to influence certain kinds of behaviour in the market.

95. I am a votary of tax reforms but it would be unwise on my part to attempt to do tax reform in a hurried or piece-meal manner. Seven months from now there will be another Budget, and there will be an occasion to visit the subject of tax reform.

Direct taxes

96. I shall begin with my direct tax proposals. Let me give you the good news first. No one with a taxable income of Rs.100,000 will be required to pay any income tax any more. It was not easy to reach this decision. While the tax rates are moderate, it is the tax slabs which cause concern. However, I am unable to alter the tax slabs because I cannot afford to lose a large amount of revenue at a time when the Government has assumed a larger responsibility for investment and welfare programmes. Out of nearly 3.4 crore persons filing income tax returns, only 2.7 crore assesseees are taxpayers. My proposal will give relief to 1.4 crore assesseees. The method that I have adopted is somewhat novel. While everyone will file his return according to the current tax slabs and tax rates, and compute his taxable income and the tax payable, any one with a taxable income of Rs.100,000 will have his income tax liability automatically rebated. I cannot give more relief, or relief across the Board, in this Budget. If compliance improves, I promise to revisit the subject.

97. I propose to give relief to certain sections of deserving tax payers. Accordingly, I propose to exempt from income tax the family pension received by widows, children and nominated heirs of members of the armed forces and the paramilitary forces killed in the course of operational duties. This is my humble salute to their supreme sacrifice.

98. I propose to extend the benefit of Section 80DD and Section 80U in respect of persons suffering from autism, cerebral palsy and multiple disability.

99. Farmers have brought to my notice that agricultural land situated in certain urban agglomerations fall under the definition of capital asset and the compensation for acquisition of such land is subjected to capital gains tax. Such compensation deserves to be exempted from capital gains tax. I propose to do so in cases where the compensation or the enhanced compensation has been received on or after April 1, 2004.

100. A new 'defined contribution' pension scheme for new entrants into Central Government service has come into effect from January 1, 2004. The tax treatment of contributions made to the scheme has engaged the attention of Government. I propose to adopt the universally accepted formula of EET: that is, the contributions will be excluded from income for tax purposes; the accruals will also be exempt from tax; and only the terminal benefits will be taxed at the applicable rate in the year of receipt.

101. I propose to withdraw a few exemptions which have outlived their utility. Interest earned from a Non-Resident (External) Account and interest paid by banks to a Non-Resident or to a Not-Ordinarily Resident on deposits in foreign currency will not be exempt from tax. Similarly, any payment made by an Indian company to acquire an aircraft or an aircraft engine on lease from a foreign state or a foreign enterprise will not be exempt from tax. These exemptions will cease prospectively from September 1, 2004.

102. Hon'ble Members are aware that I abolished the gift tax in 1997. That decision remains, but a loophole requires to be plugged to prevent money laundering. Accordingly, purported gifts from unrelated persons, above the threshold limit of Rs.25,000, will now be taxed as income. Gifts received from blood relations, lineal ascendants and lineal descendants, and gifts received on certain occasions like marriage will continue to be totally exempt.

103. In order to promote agro-processing industries, I propose to amend Section 80 IB of the Act to allow a deduction of 100 per cent of profits for 5 years and 25 per cent of profits for the next 5 years in the case of new agro-processing industries set up to process, preserve and package fruits and vegetables.

104. Investment in the manufacturing sector deserves the Government's attention. Hence, I propose to continue with the additional depreciation of 15 per cent allowed under Section 32(1)(iia) on new plant and machinery acquired or installed in an existing undertaking; however, the required increase in installed capacity will now be 10 per cent, and not 25 per cent.

105. The automobile sector has done well and needs to be encouraged. I therefore propose to notify the automobile industry as an industry entitled to 150 per cent deduction of expenditure on in-house R&D facilities.

106. The power sector also deserves tax concessions. The Electricity Act 2003 envisages unbundling of generation, transmission and distribution. In order to promote renovation and modernization of existing transmission and distribution lines, I propose to extend the benefit under Section 80 IA to projects undertaken during the period April 1, 2004 to March 31, 2006.

107. The shipping industry has demanded the levy of a tonnage tax to make it intentionally competitive. Tonnage tax will also induce more ships to fly the Indian flag. I propose to accept the request. Consequently, the concessional regime under Section 33 AC will be withdrawn and shipping companies will now have only an option to pay the tonnage tax or normal corporate tax on profits.

108. I propose to extend the benefit of Section 80 IB to new hospitals with 100 beds or more set up in rural areas. Such hospitals will be entitled to a 100 per cent deduction of their profits for a period of five years.

109. The housing industry enjoys certain benefits under Section 80 IB for projects approved before March 31, 2005. I propose to extend the time limit to March 31, 2007.

110. A small problem has plagued the reconstruction and development of existing buildings under approved plans in the city of Mumbai. Perhaps the problem is there in some other cities too. I, therefore, propose to relax the condition of minimum plot size of one acre in the case of housing projects, as long as the projects are implemented in accordance with a scheme for reconstruction or development approved by the Central or State Government.

111. Capital gains tax is another vexed issue. When applied to capital market transactions, the issue becomes more complex. Questions have been raised about the definitions of long-term and short-term, and the differential tax treatment meted to the two kinds of gains. There are no easy answers, but I have decided to make a beginning by revamping taxes on securities transactions. Our founding fathers had wisely included entry 90 in the Union List in the Seventh Schedule of the Constitution of India. Taking a cue from that entry, I propose to abolish the tax on long-term capital gains from securities transactions altogether. Instead, I propose to levy a small tax on transactions in securities on stock exchanges. The rate will be 0.15 per cent of the value of security. Thus, a transaction involving securities valued at, say, Rs.100,000 will now bear a small tax of Rs.150. The tax will be levied on the buyer. In the case of short-term capital gains from securities, I propose to reduce the rate of tax to a flat rate of 10 per cent. My calculation shows that the new tax regime will be a win-win situation for all concerned.

112. I propose to make a change in the tax on dividends distributed by mutual funds. Equity-oriented mutual funds will continue to be exempt from tax. Debt-

oriented mutual funds are now required to withhold 12.5 per cent of the income distributed to unit holders. Individuals and HUF unit holders will continue to enjoy the benefit of this rate. However, in the case of corporate unit holders, I propose a rate of 20 per cent. I am sure corporates will understand, because I am doing no more than partially closing a window of arbitrage opportunity.

113. I propose to put an end to bonus-stripping and dividend-stripping in units by making a suitable amendment to Section 94 of the Act.

114. I also propose some measures to widen the tax base and to plug revenue leakage. I do not wish to take the time of the House detailing each measure.

115. Tax deduction at source (TDS) and tax collection at source (TCS) are being extended to some more activities. Amendments are proposed to Section 40(a)(i) and Section 194 C.

116. The telecom sector enjoyed certain benefits under Section 80 IA for services commenced before March 31, 2004. Pending a detailed examination of the needs of the telecom sector, I propose to extend the terminal date to March 31, 2005.

117. Companies carrying on scientific research and development and approved by the Department of Scientific and Industrial Research before April 1, 2004 are entitled to 100 per cent deduction of profits for 10 years. On the request of the Department of Bio-Technology and pending a detailed examination, I propose to extend the terminal date to March 31, 2005.

118. New industrial undertakings in Jammu & Kashmir enjoyed 100 per cent tax exemption if they commenced production before March 31, 2004. Pending a detailed examination of the incentives required to promote industrial development in Jammu & Kashmir, I propose to extend the date to March 31, 2005.

Indirect taxes

119. Now, I turn to my indirect tax proposals. The policy signal that needs to be reiterated is that customs duties will be brought down in a measured way. It is my intention to align India's tariff structure to those of ASEAN countries. Eventually, there should be a uniform rate of tax on goods and services. During the last four years, my predecessors had adjusted excise duties and moved them towards a Central VAT rate. That process must continue. The most important goods in the manufacturing sector must therefore bear an excise duty of 16 per cent.

120. Another principle that requires to be emphasized is that where an excise duty is levied, subject to only a few exceptions, like goods when imported should attract an equivalent countervailing duty (CVD). In my tax proposals, I have, therefore, removed the exemption from CVD enjoyed by some imported goods where there is no corresponding exemption from excise duty on Indian made goods.

121. I may also point out that customs tariffs and excise duties are inter-related. While considering the tax regime for any sector, one must look at both customs duties and excise duties applicable to that sector.

122. The peak rate of customs duty was reduced to 20 per cent in January 2004. I propose to maintain the peak rate for the rest of the current fiscal year.

123. I shall now deal with specific sectors beginning with metals, minerals and industrial raw materials. Steel is the leading metal. Normally, it should bear an excise duty of 16 per cent. However, in February this year, excise duty on steel was reduced from 16 per cent to 8 per cent, but with the caveat that the decision will be reviewed when the regular budget is presented. Belying expectations, steel prices have not moderated but have risen sharply. I propose to reduce the customs duty on non-alloy steel from 15 per cent to 10 per cent and to increase the excise duty on steel from 8 per cent to 12 per cent so that the countervailing duty will also be applicable to imports. I hope to recoup some of the revenue losses since February 2004.

124. Alloy steel, copper, lead, zinc and base metals are basic raw materials used in a variety of industries. I propose to reduce the peak rate on such metals to 15 per cent. I also propose to reduce the customs duties on refractory raw minerals and mineral products like graphite, asbestos, mica and gypsum to 15 per cent. The customs duty on all catalysts will also be 15 per cent.

125. I propose certain concessions to the agriculture sector. To encourage value addition, while retaining customs duty on crude palm oil at 65 per cent, I propose to accept the recommendation of the Tariff Commission and increase the duty on refined palm oil to 75 per cent.

126. Some items of plantation machinery attract a customs duty of 5 per cent. I propose to extend the concessional rate to more items pertaining to the tea and coffee plantation sector.

127. On the excise front, I propose to make a number of concessions. Tractors attract an excise duty of 16 per cent. Hereafter, tractors will be fully exempt. Likewise, dairy machinery which attracts an excise duty of 16 per cent will be fully exempt. Hand tools such as spades, shovels, sickles etc, which currently attract a 16 per cent excise duty will also be fully exempt.

128. Excise duty on preparations of meat, poultry and fish will be reduced from 16 per cent to 8 per cent and excise duty on food grade hexane (used in the edible oil industry) will be reduced from 32 per cent to 16 per cent.

129. I propose to give some concessions to the health sector. A number of items for the disabled are already exempt from import duties or attract a concessional duty of 5 per cent. I propose that rehabilitation aids such as talking books, braille computer terminals, braille writers and typewriters, assistive

listening devices, cochlear implants and stair lifts be fully exempt from customs duty. They will also be exempt from excise duty and CVD. Crutches, wheel chairs, walking frames, artificial limbs, etc. for the disabled will also be fully exempt from customs duty. There are some restrictions on institutions for the visually-impaired and the hearing-impaired availing of import duty exemptions. I propose to remove these restrictions as well as enlarge the list of exempted appliances. Ambulances used by government and municipal hospitals alone have been allowed the concessional excise duty of 16 per cent. I propose that all ambulances registered as such will be entitled to this benefit. Diagnostic kits for detecting hepatitis B alone are exempt from excise duty. I propose to extend the exemption to kits for detection of all types of hepatitis.

130. In order to move toward the Cenvat rate, I propose to levy excise duty on contact lenses and playing cards. I also propose to increase the excise duty from 8 per cent to 16 per cent on a few items including vaccum flasks, plastic insulated ware, scented supari, prefabricated buildings, laboratory glassware, black and white television sets, populated PCBs, imitation jewellery, candles and parts of clocks and watches. Let me hasten to add that in all these cases the general SSI exemption will continue to be available, and consumers and small manufacturers will not be affected at all. Even other manufacturers will avail of Cenvat credit.

131. In order to protect matches made in the non-mechanised sector, I propose to increase the excise duty on matches made in the mechanized/semi-mechanised sector from 8 per cent without Cenvat credit to 16 per cent with Cenvat credit.

132. The Information Technology sector has, by and large, been kept out of the reach of the tax collector. Under the Information Technology Agreement, customs duty will be brought down to zero in 2005. Meanwhile, I propose to abide by the bound rates under the agreement.

133. I propose to exempt specified raw materials for manufacture of parts of cathode ray tubes and specified capital goods for manufacture of mobile handsets, plasma display panels etc. from excise duty. Specified items for manufacture of telecom grade optical fibres and cables are also proposed to be exempt from customs duty. Mobile switching centres imported by cellular mobile telephone service providers are now exempt from customs duty. I propose to extend the exemption to imports by universal access service providers.

134. Computers attract excise duty of 8 per cent. I propose to grant full exemption.

135. I propose to give some excise relief to LPG gas stoves bearing an MRP up to Rs.2000, footwear with MRP upto Rs.250 and writing instruments with MRP upto Rs.200.

136. I propose to reduce the excise duty on amusement rides from 20 per cent to 10 per cent.

137. Having been Commerce Minister, export promotion is close to my heart. I propose to extend the concessional customs duty of 5 per cent on capital goods enjoyed by the leather industry to the non-leather footwear industry too.

138. Finished leather of all kinds is exempt from customs duty. I propose to exempt patent leather also.

139. Platinum is a serious challenger to gold in the jewellery industry. Both should be treated alike. Hence, I propose to reduce the import duty on platinum from Rs.550 per 10 grams to Rs.200. I propose that rough coloured precious gemstones should be exempt from customs duty just as rough semiprecious stones are.

140. Area specific exemptions from excise duty have been granted from time to time. The North Eastern States and J&K are in a class by themselves. The exemptions enjoyed by them will continue. Sikkim, Uttaranchal and Himachal Pradesh were also granted area-based exemptions. Hon'ble Members are fully aware of the arguments in favour and the rival arguments against. I have to be fair to both sides. Accordingly, I propose that area specific exemptions enjoyed by States other than the North Eastern States and J & K will continue and be available to units set up or expanded on or before March 31, 2007.

141. I shall now deal with the most challenging tax problem that I faced this year. This relates to the textile sector. Last year, handlooms and powerlooms were brought into what is described as the Cenvat chain. The intention was good but, I am afraid, the decision did not take into account the decentralized and fragmented nature of production of fabrics in the country. Besides, the so-called Cenvat chain had nearly 40 exemptions at different stages. In fact, two exemptions were added after the decision.

142. I am conscious that the Agreement on Textiles and Clothing will come to an end on December 31, 2004. Our textile sector must, therefore, be made more efficient and competitive. Those who can compete because of their organizational strength should be allowed to compete; for the rest, we must allow more time to comply with a mandatory tax regime. Meanwhile, there must be a level playing field.

143. If I have understood correctly the mind of Hon'ble Members of Parliament, and of the leaders of various political parties, I believe that there is a universal demand to free the handloom and powerloom sectors from the Cenvat regime. After giving my anxious consideration to the complex issues, I propose to withdraw the mandatory Cenvat duty. Instead, I propose to introduce a new tax regime for the textile sector and, in this exercise, I am happy to say that I have the full support of the Minister of Textiles.

144. Let me now explain briefly the new regime.

- Firstly, the mandatory Cenvat chain will stand abolished.
- Secondly, there will be no mandatory excise duty on pure cotton, wool and silk, whether it is fibre, yarn, fabric or garment.
- Thirdly, blended textiles and pure non-cotton (polyester, viscose, acrylic and nylon) will have a different tax regime.
- Fourthly, there will be a mandatory excise duty on man-made staple fibre at 16 per cent; on polyester filament yarn (including textured yarn) at 24 per cent; and on other man-made filament yarn (including textured yarn) at 16 per cent.

145. Every manufacturer – be it handloom or powerloom or composite mill – will have the option to choose between two routes. One will be the exemption route and the other will be the Cenvat route. Under the exemption route, no excise duty will be payable at any stage (except on man-made fibre and filament yarn). Under the Cenvat route, credit can be taken for all excise duties paid at earlier stages. For the purposes of the optional Cenvat route, it is necessary to specify in the Tariff schedule the applicable excise duty rates. For the pure cotton sector, the uniform rate will be 4 per cent on yarn, fabrics, garments and made-ups. For the blended textiles sector and pure non-cotton sector, the uniform rate will be 8 per cent.

146. It is my firm belief that the millions of handloom weavers and powerloom weavers will welcome the new regime. As far as the composite mills are concerned, there is no cause for worry. They are also free to take the exemption route, but if they choose to opt for the Cenvat route, they may do so and claim Cenvat credit for all duties paid at earlier stages. Garment exporters should give the new regime a fair chance. I expect that prices of fabrics will moderate and garment exporters will stand to benefit. Their concerns, if any, can be addressed through the drawback or DEPB mechanism.

147. In course of time, it is possible that some manufacturers of handlooms and powerlooms will take advantage of the low uniform rates of duty and opt for the Cenvat route.

148. There remains the service tax. I propose to take a major step towards integrating the tax on goods and services. Accordingly, I propose to extend credit of service tax and excise duty across goods and services. In order to neutralize the revenue impact of such extension, and keeping in mind the mean Cenvat rate, I propose to enhance the rate of service tax from 8 per cent to 10 per cent.

149. 58 services have been brought under the net so far. I propose to add some more this year. These are business exhibition services; airport services; services provided by transport booking agents; transport of goods by air; survey and exploration services; opinion poll services; intellectual property services

other than copy right; brokers of forward contracts; pandal and shamiana contractors; outdoor caterers; independent TV/radio programme producers; construction services in respect of commercial or industrial constructions; and life insurance services to the extent of the risk premium. I may clarify that there is no intention to levy service tax on truck owners or truck operators. Nor, as was clarified by my predecessor, is there any intention to levy service tax on the savings part of the premium collected by an insurer.

150. I also propose that some currently taxable services should be redefined to cover all service providers falling under the same category, but I do not wish to burden this speech with the details. Exemptions granted in the case of some taxable services are proposed to be removed. The administration of service tax will be made more tax-payer-friendly. I propose to do away with the mandatory verification of self assessment and the mandatory penalty for non-registration.

151. Finally, there is the tax mandated by the NCMP. That is an education cess on all taxes. I propose to levy a cess of 2 per cent on income tax, corporation tax, excise duties, customs duties and service tax.

152. Besides my tax proposals, I have looked at another source of revenue. There are large recoverable arrears both in direct taxes and indirect taxes. Even the undisputed arrears are quite substantial. I have, therefore, assumed that I would be able to recover a tidy sum this year. A special, multi-pronged drive will be made to recover these arrears, the details of which will be announced later.

153. My tax proposals on direct taxes are expected to yield a gain of Rs.2000 crore. On the indirect taxes side, they are broadly revenue neutral.

XII. CONCLUSION

154. Mr. Speaker, Sir. The countries of the world, India included, have set for themselves the Millennium Development Goals. Our date with destiny is not at the end of the millennium, but in the year 2015. Will we achieve those goals? In the eleven years that remain, it is in our hands to shape our destiny. Progress is not always on a linear path, nor is it inevitable. Two thousand years ago, Saint Tirvalluvar said:

*"Aran Izhukkathu Allavai Neeki Maran Izhukka
Maanam Udayathu Arasu"*

(They are good rulers who observe ethics, commit no crime
and walk the path of honour and courage)

If we bring thought and passion to our governance, and walk the path of honour and courage, we can make the future happen. And this century will be India's century.

155. Sir, with these words, I commend the Budget to the House."

K. S. MENON, Jt. Secy.